फुलेश्वर गोप

बनाम

भारतीय संघ एवं अन्य

(आपराधिक याचिका संख्या 3923/2024)

(23 सितम्बर 2024)

[सी.टी. रविकुमार एवं संजय करोल, न्यायाधीश]

विचार के लिए मुद्दा

यह मुद्दा उत्पन्न हुआ कि क्या संकल्प आदेश की वैधता को किसी भी चरण में चुनौती दी जा सकती है; क्या यूएपीए की धारा 45(2) के उल्लंघन और 2008 नियमों के नियम 3 और 4 का उल्लंघन, यदि कोई हो, कार्यवाही को अवैध बनाता है, क्या वैधानिक समयसीमाओं का उल्लंघन और स्वतंत्र समीक्षा की आवश्यकता, जिसमें मानसिक परीक्षण भी शामिल है, प्रक्रिया के आवश्यक पहलू हैं; क्या अपीलकर्ता की संलिप्तता वास्तव में उन मामलों से स्वतंत्र थी जिनमें ए-6 और अन्य सदस्य आरोपी के रूप में सूचीबद्ध थे; और क्या यूएपीए की धारा 22ए के तहत वैधानिक छूट अपीलकर्ता पर लागू होती है, जो कंपनी के मामलों से अज्ञात होने का दावा करता है।

संक्षिप्त मुक़दमा

अवैध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 – धारा 45(2) – अपराधों की संज्ञान लेना – अवैध क्रियाकलाप (निवारण) (प्रस्तावना और अभियोजन की स्वीकृति) नियम, 2008 – नियम 3 और 4 – प्राधिकरण द्वारा सिफारिश करने की समयसीमा – अभियोजन की स्वीकृति की समयसीमा – अपीलकर्ता का यह कहना कि उसे आरोपी और बड़े षड्यंत्र का सदस्य बनाया गया – उस पर आरोप कि ए-6, जो एक आतंकवादी और 'पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया

(पीएलएफआइ)' का प्रमुख है, के निर्देशों पर अपीलकर्ता ने एक कंपनी बनाई, जो पीएलएफआइ की गतिविधियों के लिए प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से धन एकत्र करती थी; और अपीलकर्ता ने पीएलएफआइ के सदस्य ए-7 और ए-14 के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचकर अवैध संगठन का गठन किया – छह व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें आरोप था कि ए-6 द्वारा संबंधित बैंक में 25.83 लाख रुपए की विमुद्रीकरण की गई मुद्रा लाई गई थी – अपीलकर्ता ने स्वयं संज्ञान पत्र, अभियोजन की स्वीकृति के लिए स्वीकृति पत्र और आईपीसी एवं यूएपीए के तहत संज्ञान आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था – डिवीजन बैंच ने इन्हें रद्द करने से इनकार कर दिया – चुनौती दी गई:

निर्णय: अपीलकर्ता के खिलाफ स्वीकृति देने वाले आदेश में कोई दोष नहीं – प्राधिकरण पर यह आवश्यक नहीं है कि वह अपनी निष्कर्ष को समर्थन देने के लिए विस्तृत कारण रिकॉर्ड करे, और इस प्रकार, चुनौती दिए गए आदेश को इस आधार पर दोषपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता – चूंकि परीक्षण जारी है और अनेक गवाहों की पहले ही गवाही ली जा चुकी है, अपीलकर्ता के खिलाफ स्वीकृति की वैधता को चुनौती देने का मामला परीक्षण न्यायाधीश के समक्ष उठाने के लिए छोड़ा गया – यह कि ए-6 और अपीलकर्ता दोनों एक ही, लगातार और चल रही लेन-देन का हिस्सा हैं या नहीं, यह परीक्षण के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, न कि इस चरण में, इस न्यायालय द्वारा, और इस प्रकार इसे अपीलकर्ताओं को परीक्षण न्यायाधीश के समक्ष उठाने के लिए छोड़ दिया गया – इसके अलावा, धारा 22ए के तहत छूट की आवेदन की बात, यह परीक्षण अदालत के विचार करने का विषय है, न कि इस न्यायालय का निर्णय इस चरण में, यह देखते हुए कि परीक्षण जारी है और काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। [पैरा 18, 41, 46, 50]

अवैध गतिविधियाँ अधिनियम (निवारण), 1967 – धारा 45(2) – अपराधों का संज्ञान – :चुनौती किस चरण में – स्वीकृति आदेश की वैधता

निर्णय: स्वीकृति की वैध सबसे पहले उपलब्ध चरण में, अर्थात् ट्रायल कोर्ट से पहले चुनौती दी जानी चाहिए। यदि ऐसी चुनौती अपील के चरण में उठाई जाती है, तो चुनौती उठाने वाले व्यक्ति को यह न्यायसंगत ठहराना होगा कि उन्होंने इसे देरी से क्यों उठाया। ऐसे कारणों पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनौती के अधिकार का

दुरुपयोग न हो, जिसका उद्देश्य कार्यवाही को स्थगित या विलंबित करना हो। तथ्यों के आधार पर, यह ध्यान में रखते हुए कि यह दलील दी गई है कि ट्रायल चल रहा है और 125 में से 113 गवाहों की पहले ही गवाही हो चुकी है, अपीलकर्ता के खिलाफ स्वीकृति की वैधता पर कोई निर्णय नहीं दिया गया है और इसे ट्रायल जज के सामने उठाने के लिए छोड़ दिया गया है, जो यदि ऐसा सवाल उठता है, तो इसे शीघ्रता से निपटाएंगे। पैराग्राफ]18, 51.1]

अवैध गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967 – धारा 45(2) – अपराधों का संज्ञान – अवैध गतिविधियाँ (निवारण) (सजा की सिफारिश और स्वीकृति) नियम, 2008 – नियम 3 और 4 – प्राधिकरण द्वारा सिफारिश करने की समयसीमा – अभियोजन की स्वीकृति की समयसीमा – धारा 45(2) के अनुसार नियम 3 और 4 के साथ समयसीमा और स्वतंत्र समीक्षा की आवश्यकता, यदि आवश्यक हो, और प्रक्रिया के ऐसे पहलू, जिनका पालन न करने पर यूएपीए के तहत कार्यवाही को दोषपूर्ण कर दिया जाएगा।

निर्णय: नियम 3 और 4 में उल्लिखित समयसीमा अनिवार्य भाषा में व्यक्त की गई हैं और इसलिए इन्हें कड़ाई से पालन करना आवश्यक है – यह ध्यान में रखते हुए कि यूएपीए एक दंडात्मक कानून है, इसे कड़े तरीके से व्याख्यायित किया जाना चाहिए – वैधानिक नियमों द्वारा निर्धारित समयसीमाएँ कार्यकारी शक्ति पर निगरानी रखने का एक तरीका हैं, जो आरोपी व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है – स्वीकृति की सिफारिश करने वाले प्राधिकरण और स्वीकृति देने वाले प्राधिकरण दोनों द्वारा स्वतंत्र समीक्षा, यूएपीए की धारा 45 के अनुपालन के आवश्यक पहलू हैं – अपीलकर्ता के मामले में, जिसमें यह दावा किया गया था कि समयसीमाओं का पालन नहीं किया गया था, पहली स्वीकृति सिफारिश के एक साल से अधिक समय बाद दी गई; और सिफारिश करने वाले प्राधिकरण और केंद्रीय सरकार दोनों की ओर से कोई स्वतंत्र समीक्षा नहीं की गई, क्योंकि स्वीकृति केवल एक दिन में दी गई थी, ए-6 के खिलाफ पहली कार्रवाई और अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के बीच का अंतर निरंतर जांच का परिणाम था, क्योंकि अपीलकर्ता को उसी एफआइआर से उत्पन्न दूसरे अनुपूरक चार्जशीट में आरोपी बनाया गया था; और चूंकि जांच जारी रही, इस अंतर को घातक नहीं कहा जा सकता है, ताकि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी को अवैध या गैरकानूनी ठहराया जा सके – स्वीकृति निर्धारित समय में दी गई – इसके अतिरिक्त, यह नहीं कहा जा सकता कि विचार न किया गया था और स्वतंत्र समीक्षा का अभाव था। [पैराग्राफ 20, 28.4, 41, 51.2]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धाराएँ 218-222 – आरोपों का गलत संयोजन – दंड प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन – अपीलकर्ता का यह तर्क कि जिन लेन-देन के संबंध में उसे आरोपी बनाया गया था, वे वास्तव में उन लेन-देन से स्वतंत्र थे जिनमें ए-6 और अन्य सदस्य आरोपित थे; और यह कि एनआइए द्वारा शक्ति का अत्यधिक दुरुपयोग हुआ है और दंड प्रक्रिया संहिता की धाराएँ 218-224 का उल्लंघन हुआ है:

निर्णय: धाराएँ 218-222 का उल्लंघन नहीं हुआ – अपीलकर्ता अंतिम श्रेणी में आता है - एक ही ट्रायल में कई व्यक्ति (अपीलकर्ता ए-17 है, कुल 20 आरोपितों में से) – संयुक्त या अलग ट्रायल, ट्रायल जज द्वारा ट्रायल की शुरुआत में निर्णय लिया जाता है, यह देखते हुए कि पक्षों को कोई पूर्वाग्रह हो सकता है या नहीं और न्यायिक विलंब हो, यदि कोई हो – धारा 223 की भाषा निर्देशात्मक प्रकृति की है, जिसका संकेत 'हो सकता है' शब्द के उपयोग से होता है – यदि संयुक्त ट्रायल आयोजित किया जाता है, तो इन दो कारकों को ध्यान में रखते हुए, इसे पक्षों के लिए स्वतः पूर्वाग्रहजनक नहीं कहा जा सकता है – आरोप है कि ए-6, जो पीएलएफआइ का प्रमुख है, विभिन्न व्यक्तियों से पैसे वसूलता है और जिस कंपनी ए-20 का अपीलकर्ता निदेशक है, का उपयोग उन अवैध कार्यों से प्राप्त धन को वैध बनाने के लिए किया जाता है – हालांकि, अपीलकर्ता का यह तर्क कि ए-6 पर लगाए गए आरोपों और उन लेन-देन के बीच कोई संबंध नहीं है, जिनके कारण उसे आरोपी बनाया गया है, जबकि अभियोजन पक्ष का कहना है कि ए-6 और ए-17 एक ही, निरंतर चल रहे लेन-देन का हिस्सा हैं – यह कि क्या वास्तव में ऐसा है, यह प्रश्न ट्रायल में प्रस्तुत किए गए सबूतों के आधार पर तय किया जाएगा, न कि इस चरण में, इस अदालत द्वारा – इसलिए, यह अपीलकर्ताओं पर निर्भर है कि वे यह मुद्दा ट्रायल जज के समक्ष उठाएं, जो यदि ऐसा सवाल उठता है, तो इसे उचित चरण में शीघ्रता से निपटाएंगे। [पैराग्राफ 44.3, 45, 46, 52.1]

अवैध गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967 – धारा 22ए – कंपनियों द्वारा किए गए अपराध – धारा 22ए के तहत वैधानिक छूट – अपीलकर्ता जो कंपनी के मामलों से अनजान होने का दावा करता है, पर लागूता:

निर्णय: यह कि धारा 22ए के तहत छूट लागू होती है या नहीं, यह एक ऐसा मामला है जिसे प्रमाणों के माध्यम से स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि छूट का दावा करने वाले व्यक्ति को

यह सिद्ध करना होगा कि या तो वह उस कंपनी के मामलों का प्रभारी नहीं था, जिसने कथित रूप से अपराध किया है, या उसने अपराध के कमीशन को रोकने के लिए उचित प्रयास किए थे – यह ट्रायल कोर्ट के विचार करने का मामला है, न कि इस अदालत के लिए इस चरण में निर्णय लेने का, यह ध्यान में रखते हुए कि ट्रायल जारी है और काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। [पैराग्राफ 50, 52.2]

अवैध गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967 – धारा 22ए – कंपनियों द्वारा किए गए अपराध – धारा 22ए की लागूता:

निर्णय धारा :22ए के लागू होने के लिए, अपराध कंपनी द्वारा किया गया होना चाहिए; वे सभी व्यक्ति जो अपराध के समय कंपनी के मामलों पर नियंत्रण या जिम्मेदारी रखते थे, उन्हें दोषी माना जाएगा; हालांकि, ऐसे व्यक्ति को दोष से बचाया जा सकता है यदि वे यह साबित कर सकें कि ऐसा कृत्य उनकी जानकारी में नहीं था और उन्होंने उस अपराध को होने से रोकने के लिए उचित सावधानी बरती थी। धारा 22ए यह भी प्रावधान करती है कि यदि यह प्रमाणित हो सके कि कंपनी द्वारा किया गया अपराध किसी प्रमोटर, निदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति, साजिश या लापरवाही के कारण हुआ था, तो उन्हें दोषी ठहराया जाएगा। पैराग्राफ]48]

अवैध गतिविधियाँ अधिनियम (निवारण), 1967 – धारा 45(2) – अपराधों का संज्ञान अवैध – सजा की सि) (निवारण) गतिविधियाँफारिश और स्वीकृतिनियम (, 2008 – नियम 3 और 4 – प्राधिकरण द्वारा सिफारिश करने की समयसीमा – अभियोजन की स्वीकृति की समयसीमा – समयसीमा, क्या निर्देशात्मक या अनिवार्य:

निर्णयसामान्य रूप से :, वैधानिक ढांचे के हिस्से के रूप में समयसीमाएँ आपराधिक जांच, अभियोजन और ट्रायल की एक प्रभावी, कुशल और केंद्रित प्रणाली के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इन कानूनी प्रक्रियाओं के सुचारू कार्यान्वयन में सभी संबंधित पक्षों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए ताकि समयसीमाओं को पूरा किया जा सके। ये समयसीमाएँ शीघ्र न्याय के अधिकार के अभिन्न भाग हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सुनिश्चित किया गया है। पैराग्राफ] 22]

'मनन की प्रक्रिया' – संकल्पना:

निर्णय: मनन की प्रक्रिया किसी भी न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक आदेश का हिस्सा होना चाहिए। इसे प्रदर्शित करने के लिए, ऐसी प्राधिकरण के सामने प्रस्तुत सामग्री का विचार करना प्रतिबिंबित होना चाहिए। चूंकि यह एक मानसिक प्रक्रिया है, इसलिए इसे समझाने के लिए किसी सूत्र को निर्धारित करना उचित नहीं है, क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दंडात्मक कानूनों के संदर्भ में, जिन प्राधिकरणों को अभियोजन की स्वीकृति देने से पहले सामग्री का मूल्यांकन करना होता है, या स्वीकृति देने का कार्य स्वयं, उन्हें प्रस्तुत की गई सामग्री के प्रत्येक पहलू पर अपना मनन करना चाहिए ताकि वे सही निष्कर्ष पर पहुँच सकें, विशेष रूप से क्योंकि इस कार्य का प्रभाव अत्यधिक होता है। स्वीकृति देने या न देने का निर्णय ही ऐसे कड़े कानूनों जैसे यूएपीए या टाडा की कार्यवाही को शुरू करता है। [पैराग्राफ 25, 26]

अवैध गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967 – धारा 45(2) – अपराधों का संज्ञान – यूएपीए के तहत स्वीकृति की प्रक्रिया:

निर्णयन्यायालय को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृति के बिना संज्ञान लेने : की अनुमति नहीं है, और यह स्वीकृति केवल तभी दी जा सकती है जब केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण की रिपोर्ट पर विचार किया गया हो यह –प्राधिकरण एक स्वतंत्र समीक्षा करेगा और एक समयबद्ध तरीके से सरकार को सिफारिश करेगा। यदि कोई न्यायालय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना संज्ञान लेता है, तो यह अधिनियम के विपरीत होगा और इसलिए कानून में गलत माना जाएगा यह स्वीकृति केवल सरकार का कार्य नहीं है –, बल्कि इसे केवल एक स्वतंत्र निकाय द्वारा प्रमाणों की स्वतंत्र समीक्षा करने के बाद ही दिया जा सकता है, जो कि सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो। पैराग्राफ]28, 28.1]

अवैध गतिविधियाँ नियम (सजा की सिफारिश और स्वीकृति) (निवारण), 2008 – नियम 3 और 4 – सिफारिश करने की समयसीमा :निर्माण – अभियोजन की स्वीकृति की समयसीमा –

निर्णय: दंडात्मक कानूनों को कड़ाई से व्याख्यायित किया जाना चाहिए – वैधानिक शक्तियों से उत्पन्न होने वाले नियमों का प्रभाव एक कानून जैसा होता है – यूएपीए की धारा 52 केंद्रीय

सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है – धारा 52(2)(इइ) सरकार को धारा 45 के तहत सिफारिश और स्वीकृति देने के लिए समय निर्धारित करने का अधिकार देती है – नियम स्पष्ट रूप से दोनों मामलों में 'shall' शब्द का उपयोग करते हैं और दोनों गतिविधियों, यानी सिफारिश करने और स्वीकृति देने के लिए एक विशिष्ट समयसीमा निर्धारित करते हैं – कड़ी व्याख्या के मामलों में, जब समयसीमा निर्धारित की जाती है, साथ ही 'shall' शब्द का प्रयोग किया जाता है, और विशेष रूप से जब यह यूएपीए जैसे कानून के संदर्भ में होता है, तो इसे केवल एक तकनीकीता या औपचारिकता नहीं माना जा सकता – यह विधानमंडल की स्पष्ट मंशा को दर्शाता है – यह बाध्यता है, और उस बाध्यता को पूरा करने के लिए एक समयसीमा प्रदान की गई है – जबकि यह विधान अवैध गतिविधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक प्रथाओं को रोकने के उद्देश्य से है और इसके अनुसार सरकार को सभी प्रक्रियाओं और कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान करता है, उसी समय अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए – समय केवल एक स्वतंत्र समीक्षा के द्वारा एकत्र किए गए सामग्री पर विचार करने के लिए है और फिर सिफारिश बनाने के बाद, स्वीकृति देने वाली प्राधिकरण द्वारा सामग्री और सिफारिश पर विचार किया जाता है, ताकि स्वीकृति दी जाए या न दी जाए – यह स्वयं जांच प्रक्रिया के लिए नहीं है, जो स्वाभाविक रूप से एक समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि इसमें कई चर शामिल होते हैं – ऐसी स्थितियों में समयसीमाएँ एक आवश्यक जांच और संतुलन के पहलू के रूप में कार्य करती हैं और यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं – विधान की मंशा स्पष्ट है – वैधानिक शक्तियों से बनाए गए नियम दोनों एक अनिवार्यता और समयसीमा निर्धारित करते हैं – इसे अनुसरण किया जाना चाहिए – 2008 के नियमों के तहत नियम 3 और 4 में उल्लेखित समयसीमा का कड़ाई से पालन किया जाएगा। [पैराग्राफ 31, 32, 33]

अवैध गतिविधियाँ अधिनियम (निवारण), 1967 – धारा 45(2) – अपराधों का संज्ञान स्वतंत्र – यह – अर्थ – समीक्षा तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि सिफारिश करने वाली और स्वीकृति देने वाली दोनों प्राधिकरणों ने अपनीअपनी भूमिकाओं को केवल एक दिन में पूरा किया-, इस प्रकार स्वतंत्र समीक्षा की आवश्यकता, जिसे दोनों प्राधिकरणों द्वारा किया जाना चाहिए, पूरी नहीं की गई, जिससे संबंधित स्वीकृति अवैध हो गई:

निर्णय: स्वतंत्र समीक्षा का अर्थ है जांच अधिकारी द्वारा एकत्रित की गई सामग्री का विचार करना या उसका अध्ययन करना, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि क्या यूएपीए के प्रावधानों के तहत कार्यवाही जारी रखने के लिए स्वीकृति दी जानी चाहिए या नहीं। इसी तरह, अगले चरण में, स्वीकृति देने वाली प्राधिकरण को एकत्रित की गई सामग्री और सिफारिश करने वाली प्राधिकरण द्वारा खींचे गए निष्कर्षों पर विचार करना चाहिए, जब वह स्वीकृति प्रदान कर रही हो। इस प्राधिकरण की स्वतंत्रता अनिवार्य है, इसके बिना इसका उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अपीलकर्ता का यह तर्क कि सिफारिश और स्वीकृति देने में लिया गया कम समय यह दर्शाता है कि मनोयोग से विचार नहीं किया गया और स्वतंत्र समीक्षा की कमी है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी भी प्राधिकरण की क्षमता पर कोई प्रश्न नहीं उठ सकता, जैसा कि सही रूप से नहीं उठ सकता। इसलिए, केवल यह तर्क कि समय कम लिया गया था या यह कि अन्य आदेशों में समान शब्दों का प्रयोग किया गया, स्वीकृति की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठा सकता। इस प्रकार, स्वतंत्र समीक्षा और मनोयोग से विचार करना ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें प्रमाण के माध्यम से निर्धारित किया जाना चाहिए और इसे परीक्षण के चरण में उठाया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन आधारों पर कार्यवाही अपने तार्किक और कानूनी निष्कर्ष तक पहुंचने में कोई अनावश्यक देरी न हो। यदि यह देरी से उठाया जाता है, तो अदालत को इस देरी के कारणों पर विचार करना चाहिए, इससे पहले कि वह ऐसे आपत्तियों की मेरिट में जाए। इन आधारों पर देरी से की गई चुनौतियों को परीक्षण में रुकावट के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, और न ही इन्हें वैध रूप से किए गए अभियोजन और परीक्षणों से बचने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को न्यायिक समीक्षा के समान पैमाने पर न्यायिक या न्यायिक-रूप से न्यायिक आदेश के रूप में परखा नहीं जा सकता। जबकि बाद के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी विशेष निर्णय पर पहुंचने के लिए कारणों को दर्ज करें, पहले के लिए यह पर्याप्त है कि यह दिखाया जाए कि आदेश पारित करने वाली प्राधिकरण ने प्रासंगिक तथ्यों और सामग्री पर मनोयोग से विचार किया। इस प्रकार, अपीलकर्ता के खिलाफ स्वीकृति देने वाले आदेश में कोई खामी नहीं है। ऐसे प्राधिकरण पर यह अनिवार्य नहीं है कि वह अपने निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए विस्तृत कारण दर्ज करे और इस प्रकार, चुनौती दिए गए आदेशों को इस आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। [पैराग्राफ 37, 40, 41]

शब्द और वाक्यांश शब्द –'स्वतंत्र' – अर्थ:

निर्णयकिसी क्रिया या मूल्यांकन को इस तर :ह से किया जाता है जो स्वतंत्र रूप से खड़ा हो या जो किसी अन्य तत्व, जैसे कि किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा की गई पिछली समीक्षा या मूल्यांकन पर निर्भर न हो, ताकि यह अपने निष्कर्ष पर पहुंच सके स्वतंत्रता –, जो स्वतंत्र होने की अवस्था है, इसे समझने में सहायक होगी समीक्षा –, एक अवधारणा के रूप में, को समझा जाना चाहिए, क्योंकि ये दो पहलुओं का मिलाजुला होना ही 'स्वतंत्र समीक्षा' शब्द को समझने का आधार बनाता है –'स्वतंत्र समीक्षा' शब्द का अर्थ है, किसी चीज़ की पुनः जांच, परीक्षा या आलोचना, जो किसी अन्य तत्व या प्राधिकरण के नियंत्रण में या निर्भर नहीं होती। पैराग्राफ] 35-37]

उद्धृत किया गया निर्णय

ए.आर. अंतुले बनाम रामदास श्रीनिवास नायक **[1984] 2 एससीआर 914 : (1984) 2 एससीसी 500** – अनुसरण किया।

कर्नाटक राज्य बनाम एस] *सुब्बेगौड़ा* .**2023] 11 एससीआर 19 : 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 911**; *नसीब सिंह बनाम पंजाब राज्य*] **2021] 13 एससीआर 566 : (2022) 2 एससीसी 89**; *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम परस नाथ सिंह*] **2009] 8 एससीआर 85 : (2009) 6 एससीसी 372**; *राज्य दिल्ली) (एनसीटी बनाम नवजोत संधू*]**2005] सप्ली .2 एससीआर 79: (2005) 11 एससीसी 600**; *भारत संघ बनाम देवकी नंदन अग्रवाल*] **1991] 3 एससीआर 873: 1992 सप्ली) .1) एससीसी 323**; *भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान बनाम प्राइस वाटरहाउस*] **1997] सप्ली .2 एससीआर 267 : (1997) 6 एससीसी 312**; *शिव शक्ति सहकारी हाउसिंग सोसाइटी बनाम स्वराज डेवलपर्स*] **2003] 3 एससीआर 762 : (2003) 6 एससीसी 659** – पर भरोसा किया गया।

प्रदीप राम बनाम झारखंड राज्य और अन्य **[2019] 8 एससीआर 824 : (2019) 17 एससीसी 326**; *भूषण कुमार और अन्य बनाम राज्य (दिल्ली एनसीटी)* **[2012] 2 एससीआर 696 : (2012) 5 एससीसी 424**; *गुजरात राज्य बनाम अफरोज़ मोहम्मद हसनफत्ता* **[2019] 1 एससीआर 1104 : (2019) 20 एससीसी 539**; *अशरफ खान बनाम गुजरात राज्य* **(2012) 11 एससीसी 606**; *गुजरात राज्य बनाम अनवर उस्मान सुम्भनिया* **[2019] 2 एससीआर 749 :**

(2019) 18 एससीसी 524; *अनिरुद्धसिंहजी करनसिंहजी जाडेजा बनाम गुजरात राज्य* [1995] सप्ली. 2 एससीआर 637 : (1995) 5 एससीसी 302; *रामभाई नाथाभाई गधवी बनाम गुजरात राज्य* [1997] सप्ली. 3 एससीआर 356 : (1997) 7 एससीसी 744; *सीनी नैनार मोहम्मद बनाम राज्य* [2017] 3 एससीआर 312 : (2017) 13 एससीसी 685; *जमीरुद्दीन अंसारी बनाम सीबीआई* [2009] 7 एससीआर 759 : (2009) 6 एससीसी 316; *सिविल लिबर्टीज के लिए पीपल्स यूनियन बनाम भारत संघ* [2004] 1 एससीआर 232 : (2004) 9 एससीसी 580; *संजय दत्त बनाम राज्य सीबीआई के माध्यम से* [1994] सप्ली. 3 एससीआर 263 : (1994) 5 एससीसी 410; *अरुप भुयान बनाम असम राज्य* [2023] 8 एससीआर 496 : (2023) 8 एससीसी 745; *केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम अशोक कुमार अग्रवाल* (2014) 14 एससीसी 295; *प्रकाश सिंह बादल बनाम पंजाब राज्य* [2006] सप्ली. 10 एससीआर 197 : (2007) 1 एससीसी 1; *दिनेश कुमार बनाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया* [2011] 13 एससीआर 260 : (2012) 1 एससीसी 532; *केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य बनाम प्रमिला वीरेंद्र कुमार अग्रवाल* (2020) 17 एससीसी 664; *पी.के. प्रधान बनाम सिक्किम राज्य* [2001] 3 एससीआर 1119 : (2001) 6 एससीसी 704; *रंगकू दत्ता बनाम असम राज्य* [2011] 8 एससीआर 639 : (2011) 6 एससीसी 358; *हुसैन गढ़ियाली बनाम गुजरात राज्य* [2014] 9 एससीआर 364 : (2014) 8 एससीसी 425; *महेश करिमन तिरकी बनाम महाराष्ट्र राज्य,* विशेष अनुमति याचिका (क्रि.) संख्या 11072-11073/2022; *बिनोद गंझू बनाम भारत संघ,* डब्ल्यू.पी. (क्रि.) 308/2022; *राजस्थान राज्य बनाम मोहिनुद्दीन जमाल अल्वी* (2016) 12 एससीसी 608; *रूपेश बनाम केरल राज्य,* 2022 एससीसी ऑनलाइन केर 1372; *विजय राजमोहन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (एंटी-करप्शन ब्रांच)* [2022] 19 एससीआर 563 : (2023) 1 एससीसी 329; *स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम प्रवर्तन निदेशालय* [2005] सप्ली. 1 एससीआर 49 : (2005) 4 एससीसी 530; *झारखंड राज्य बनाम अंबय सीमेंट्स* [2004] सप्ली. 6 एससीआर 125 : (2005) 1 एससीसी 368; *मनजीत सिंह बनाम सीबीआई* [2011] 1 एससीआर 997 : (2011) 11 एससीसी 578; *तमिलनाडु राज्य बनाम सिवरासन* [1996] सप्ली. 8 एससीआर 243 : (1997) 1 एससीसी 682; *प्रिय इंदोरिया बनाम कर्नाटक राज्य* [2023] 15 एससीआर 525 : (2024) 4 एससीसी 749; *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनबोधन लाल श्रीवास्तव* [1958] 1 एससीआर 533 : 1957 एससीसी ऑनलाइन एससी 4; *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बाबू राम उपाध्याय* [1961] 2 एससीआर 679 : 1960 एससीसी ऑनलाइन एससी 5; *बच्चन देवी बनाम नगर निगम, गोरखपुर* [2008]

2 एससीआर 424 : (2008) 12 एससीसी 372; *विजय धनुका बनाम नजीमा मम्ताज* **[2014] 4 एससीआर 171 : (2014) 14 एससीसी 638**; *भारत संघ बनाम ए.के. पांडे* **(2009) 10 एससीसी 552**; *सी.एस. कृष्णमूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य* **[2005] 2 एससीआर 1163 : (2005) 4 एससीसी 81**; *मध्य प्रदेश राज्य बनाम हरिशंकर भगवान प्रसाद त्रिपाठी* **[2010] 9 एससीआर 1148 : (2010) 8 एससीसी 655**; *महाराष्ट्र राज्य बनाम महेश जी. जैन* **[2013] 3 एससीआर 850 : (2013) 8 एससीसी 119**; *जजबीर सिंह बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी* **[2023] 6 एससीआर 1 : 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 543**; *पंजाब राज्य बनाम मोहम्मद इकबाल भट्टी* **[2009] 11 एससीआर 790 : (2009) 17 एससीसी 92**; *बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा,* **1992 सप्ली. (1) एससीसी 222**; *पुलिस अधीक्षक (सीबीआई) बनाम दीपक चौधरी* **[1995] सप्ली. 2 एससीआर 818 : (1995) 6 एससीसी 225**; *मोहम्मद इकबाल एम. शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य* **[1998] 2 एससीआर 734 : (1998) 4 एससीसी 494**; *बलबीर बनाम हरियाणा राज्य* **[1999] सप्ली. 4 एससीआर 120 : (2000) 1 एससीसी 285**; *आर. दिनेशकुमार बनाम राज्य* **[2015] 5 एससीआर 605 : (2015) 7 एससीसी 497**; *एस.एम.एस. फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला* **[2007] 2 एससीआर 862 : (2005) 8 एससीसी 89**; *सुसेला पद्मावती अम्मा बनाम भारती एयरटेल लिमिटेड* **[2024] 3 एससीआर 647 : 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 311**; *एन. रंगाचारी बनाम बीएसएनएल* **[2007] 5 एससीआर 329 : (2007) 5 एससीसी 108**; *सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम एशियन ग्लोबल लिमिटेड* **[2010] 7 एससीआर 694 : (2010) 11 एससीसी 203**; *गुनमाला सेल्स (पी) लिमिटेड बनाम अनु मेहता* **[2014] 10 एससीआर 1117 : (2015) 1 एससीसी 103**; *राजेश वीरेन शाह बनाम रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड* **(2024) 4 एससीसी 305** – उल्लेख किया गया।

मॉन्ट्रियल स्ट्रीट रेलवे कंपनी बनाम नॉर्मैंडिन, **एलआर (1917) एसी 170** – का भी उल्लेख किया गया।

उद्धृत पुस्तकें और पत्रिकाएँ

मैक्सवेल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स)11वां संस्करण(; कैम्ब्रिज शब्दकोश; मेरीयम वेबस्टर शब्दकोश; ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी; बर्टन की लीगल थेसॉरस तीसरा संस्करण पृष्ठ 473

अधिनियमों की सूची

गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम (रोकथाम), 1967; गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) नियम (अभियोग की सिफारिश और स्वीकृति), 2008; आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1908; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008

कीवर्ड्स की सूची

स्वीकृति आदेश की वैधता; वैधानिक समयसीमाओं का उल्लंघन; स्वतंत्र समीक्षा की आवश्यकता; विचार का अनुप्रयोग; यूएपीए की धारा 22ए के तहत वैधानिक छूट; प्राधिकरण द्वारा सिफारिश के लिए समय सीमा; अभियोजन की स्वीकृति के लिए समय सीमा; आतंकवादी और पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रमुख (पीएलएफआई); पीएलएफआई की गतिविधियां; गैरकानूनी संघ; अमान्य मुद्रा; स्वतः संज्ञान पत्र को रद्द करना; जांच; स्वीकृति पत्र; दंडात्मक कानून; सख्त व्याख्या; स्वीकृति प्रदान करना; विचार का अभाव; सीआरपीसी का उल्लंघन; समयसीमा, निदेशात्मक या अनिवार्य; यूएपीए के तहत स्वीकृति की प्रक्रिया; समयसीमा का कड़ाई से पालन।

केस का उद्भव

आपराधिक अपीलीय अधिकार क्षेत्र: आपराधिक अपील संख्या 3923/2024

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के 21.03.2023 को डब्लूपीसीआर संख्या 443/2022 में दिए गए निर्णय और आदेश से उत्पन्न।

पक्षों के लिए उपस्थितियाँ

अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता :
बालाजी श्रीनिवासन, रोहन देवान, विश्वादित्य शर्मा, श्रीमती हर्षा त्रिपाठी।

प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता:
विक्रमजीत बनर्जी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्रीमती स्वारूपमा चतुर्वेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती रुक्मिणी बोबडे, राघव शर्मा, माधव सिंघल, श्रीमती ज़ीनत मलिक, अरविंद कुमार शर्मा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

संजय करोल, न्यायाधीश

अनुमति प्रदान की गयी|

2. इस अपील में विशेष अनुमति से चुनौती दी गई है झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के 21 मार्च 2023 के निर्णय में, जो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 443/2022 में दिया गया था, जिसमें माननीय खंड पीठ ने मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया –

(क) स्वतः संज्ञान पत्र संख्या एफ संख्या 11011/51/2017/IS-IV दिनांक 16 जनवरी, 2018, जो बेरो थाना मामला संख्या 67/2016 दिनांक 10 नवम्बर, 2016 की जांच से संबंधित है;

(ख) स्वीकृति पत्र संख्या 11011/51/2017/एनआइए दिनांक 22 जुलाई, 2020, जो वर्तमान अपीलकर्ता के अभियोजन के लिए स्वीकृति प्रदान करता है, जो आर.सी.-02/2018/एनआइए/डीएलआइ में आरोपी संख्या 17 हैं; और

(ग) संज्ञान आदेश दिनांक 25 जुलाई, 2020, भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 17, 18, 21 और 22, सीएलए अधिनियम, 1908 की धारा 17(i) और (ii) के तहत, और आरोप 16 मार्च, 2021 को निर्धारित किए गए, जो माननीय विशेष न्यायाधीश, एनआइए, रांची की अदालत में लंबित है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रारंभ में स्वीकृति के संदर्भ में भी रद्दीकरण की मांग की गई थी, जो पत्र संख्या 06/Avi-01/21/2017-2637 दिनांक 12 मई, 2017 के माध्यम से गृह, कारागार और आपदा प्रबंधन विभाग, रांची के प्रधान सचिव द्वारा दी गई थी। हालांकि, अपील में चुनौती दिए गए निर्णय के पैराग्राफ 4 में यह रिकॉर्ड किया गया है कि यह विशिष्ट प्रार्थना उसके सामने प्रस्तुत नहीं की गई थी।

पृष्ठभूमि तथ्य

3. वर्तमान अपील के निपटान के लिए आवश्यक तथ्य, अनावश्यक विवरण से मुक्त, इस प्रकार हैं- :

3.1 यह आरोप है कि अपीलकर्ता, फूलेश्वर गोप1, पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया2 का

सहयोगी है और उसे इस बात का ज्ञान है कि दिनेश गोपे उर्फ कुलदीप यादव उर्फ बैंकू (ए-6) एक आतंकवादी है और पीएलएफआइ का प्रमुख है, जो जबरन वसूली के माध्यम से धन एकत्र करता है। इसके अतिरिक्त, यह भी आरोप है कि उसने आपराधिक साजिश रची और पीएलएफआइ के सदस्यों, अर्थात् दिनेश गोपे, सुमंत कुमार उर्फ पवन कुमार (ए-7) और हीरा देवी उर्फ अनीता देवी (ए-14) के साथ एक गैरकानूनी संघ गठित किया।

3.2 ए-6 के निर्देश पर, यह आरोप है कि अपीलकर्ता ने ए-14 के साथ मिलकर एक कंपनी मेसर्स शिव शक्ति समृद्धि इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड (ए-20) का गठन किया, जो अधिकतर एक साझेदारी के रूप में थी। इस कंपनी का बैंक खाता ए-6 के निर्देशों पर पीएलएफआइ की गतिविधियों के लिए वैध या अवैध स्रोतों से धन एकत्र करने के लिए सीधे या परोक्ष रूप से इस्तेमाल किया गया था।

3.3 10 नवम्बर, 2016 को बेरो, झारखंड में एफआइआर संख्या 67/2016 दर्ज की गई, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 212, 213/34, 414 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम3, 1967 की धारा 13, 17, 40 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1908 की धारा 17 के तहत छह व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे, यह आरोप था कि 25.83 लाख रुपये की विमुद्रीकृत मुद्रा ए-6 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की संबंधित शाखा में लायी गई थी।

3.4 9 जनवरी, 2017 को, आरोप पत्र संख्या 01/2017 दाखिल किया गया और माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने इसका संज्ञान लिया। 18 मार्च, 2017 को, रांची के उपकलेक्टर ने अभियोजन के लिए स्वीकृति मांगी, जिसे गृह, कारागार और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव द्वारा स्वीकृति दी गई। हालांकि, इसके बाद, भारत सरकार के गृह मंत्रालय4 ने 16 जनवरी, 2018 को संबंधित मामले में स्थानांतरण आदेश जारी किया और इस प्रकार एफआइआर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी5 के तहत फिर से पंजीकृत किया गया। गृह मंत्रालय ने 16 अक्टूबर, 2019 को स्वतः संज्ञान लेते हुए बारह अभियुक्तों, ए-1 से ए-12 के खिलाफ स्वीकृति दी।

1. इसे आगे A-17 के रूप में संदर्भित किया जाएगा।
2. संक्षिप्त रूप में 'पीएलएफआइ'
3. संक्षिप्त रूप में 'यूएपीए'
4. संक्षिप्त रूप में 'एमएचए'
5. संक्षिप्त रूप में 'एनआइए'

3.5 21 अक्टूबर, 2019 को, एनआइए द्वारा एक अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसमें अपीलकर्ता को अभियोजन के गवाह के रूप में नामित किया गया, जिसे पीडब्लू-65 के रूप में प्रस्तुत किया गया। 5 नवम्बर, 2019 को, विशेष न्यायाधीशएनआइए ने उसी का संज्ञान लिया।

3.6 इसके बाद, अपीलकर्ता को 13 जुलाई, 2020 को गिरफ्तार किया गया। 22 जुलाई, 2020 को, स्वतः संज्ञान लेते हुए सात अतिरिक्त व्यक्तियों ए-13 से ए-20) के खिलाफ स्वीकृति जारी की गई, जिसमें अपीलकर्ता ए-17 है। अगले दिन, यानी 23 जुलाई, 2020 को, यूएपीए की धारा 17, 18, 21 और 22सी के तहत दूसरा अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल किया गया।

3.7 14 नवम्बर, 2022 को, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें 22 जुलाई, 2020 के स्वीकृति आदेश, 25 जुलाई, 2020 के आदेश द्वारा दूसरे अतिरिक्त आरोप पत्र का संज्ञान लेने और 16 मार्च, 2021 के आदेश द्वारा आरोप तय करने की प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की गई।

3.8 इसी पृष्ठभूमि में, अपील में चुनौती दिए गए निर्णय को पारित किया गया।

<u>चुनौतीपूर्ण निर्णय</u>

4. उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम6, 2008 की धारा 6(2) और)3) का पालन नहीं किया गया, जिससे इसमें उल्लिखित वैधानिक समयसीमाओं की पूरी तरह अनदेखी की गई। इसके अतिरिक्त, यह भी तर्क दिया गया कि यूएपीए की धारा 45(1) और)2) का पालन नहीं किया गया।

5. उच्च न्यायालय ने अपने विचार के लिए निम्नलिखित मुद्दे निर्धारित किए:

"8.....
(i) क्या केंद्रीय सरकार के पास यह स्वतः अधिकार है कि वह जिला पुलिस द्वारा जांच पूरी किए जाने के बाद जांच को एनआईए को सौंपे?

---

6. इसे आगे एनआइए 2008 के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

(ii) क्या 22.07.2020 को भारत सरकार के उप सचिव द्वारा यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 45(2) के तहत प्राधिकृत शक्ति का उपयोग करके जारी किया गया स्वीकृति आदेश किसी अवैधता से प्रभावित है?

(iii) क्या 120बी भारतीय दंड संहिता के तहत और यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 17, 18, 21 और 22सी तथा सीएलए अधिनियम, 1908 की धारा 17() और (ii) के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञान लेने का आदेश किसी दोष से ग्रस्त है?

5.1 पहले मुद्दे का निर्णय करते हुए, न्यायालय ने *प्रदीप राम बनाम राज्य झारखंड और अन्य*7 मामले पर निर्भरता जताई, विशेष रूप से इसके पैराग्राफ 49 पर, और यह निष्कर्ष निकाला कि एनआईए को आगे की जांच करने और पूरक रिपोर्ट (रिपोर्टों) प्रस्तुत करने का अधिकार है, और इस पर कोई क्षेत्राधिकार की कमी नहीं है।

5.2 दूसरे मुद्दे में स्वीकृति की वैधता और उचितता को चुनौती दी गई थी, यह तर्क देते हुए कि *गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) (अभियोग की सिफारिश और स्वीकृति) नियम*8, *2008* के नियम 3 का पालन नहीं किया गया। न्यायालय ने 22 जुलाई, 2020 के स्वीकृति आदेश की सामग्री का उल्लेख किया, जो उनके समक्ष चुनौती दी गई थी, और फिर यह निष्कर्ष निकाला कि नियम 3 में निर्धारित समयसीमा का कड़ाई से पालन किया गया है।

5.3 तीसरे मुद्दे में यह प्रश्न था कि क्या संज्ञान आदेश विचार के अभाव से प्रभावित है। न्यायालय ने *भूषण कुमार और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)*9 *और राज्य गुजरात बनाम अफरोज मोहम्मद हसनफत्ता*10 मामलों में दिए गए निर्णयों का संदर्भ लिया, ताकि मजिस्ट्रेट के पास आदेश जारी करने या समन भेजने के स्तर पर अधिकार की जांच की जा सके। अंत में, न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि माननीय विशेष न्यायाधीश का दृष्टिकोण, जो उन्होंने मामले की डायरी, अभियोजन गवाहों के बयान, अन्य दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं के आधार पर सामग्री को देखा, इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. उच्च न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्षों से असंतुष्ट, अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

---

7 [2019] 8 एससीआर 824 : (2019) 17 एससीसी 326

8 आगे '2008 नियम' के रूप में संदर्भित।

9 [2012] 2 एससीआर 696 : (2012) 5 एससीसी 424

10 [2019] 1 एससीआर 1104 : (2019) 20 एससीसी 539

प्रस्तुत किए गए तर्क

7. हमने अपीलकर्ता के लिए श्री बालाजी श्रीनिवासन, अधिवक्तारिकॉर्ड-ऑन-, और भारत सरकार के लिए श्री विक्रमजीत बनर्जी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और श्रीमती स्वारूपमा चतुर्वेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता से दलीलें सुनीं।भी आधारित है, इसलिए अपीलित दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश रद्द और निरस्त किया जाना उचित है।

8. चुनौतीपूर्ण निर्णय पर आपत्ति जताते हुए, अपीलकर्ताओं ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं।

8.1 यूएपीए की धारा 45 को 2008 के नियम 3 और 4 के साथ पढ़ने पर स्वीकृति देने की विस्तृत प्रक्रिया और उस प्रक्रिया के तहत समयसीमा प्रदान की जाती है, जिसके भीतर स्वीकृति दी जानी चाहिए। चुनौतीपूर्ण स्वीकृति वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि यह घटना के 2 साल 11 महीने बाद और 12 मई, 2017 के पत्र के 2 साल 6 महीने बाद जारी की गई।

8.2 यूएपीए की धारा 45 के उपबंध (2) का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि स्वीकृति प्रदान करते समय 'स्वतंत्र समीक्षा' की आवश्यकता का पालन नहीं किया गया। यह तर्क दिया गया है कि स्वीकृति आदेश यांत्रिक रूप से पारित किया गया था, जिसमें कोई कारण या विचारण नहीं दिया गया। आदेश सांचो और सामान्य हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 45 में प्रत्येक चरण में स्वतंत्र जांच और विचारण की आवश्यकता है - पहले द्वारा प्राधिकृत एजेंसी, फिर स्वतंत्र एजेंसी द्वारा और अंत में स्वीकृति प्रदान करने वाली संस्था द्वारा। चूंकि इस मामले में यह पालन नहीं किया गया, इसलिए स्वीकृति आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं।

8.3 स्वीकृति की वैधता एक ऐसा प्रश्न है जिसे प्रक्रिया के किसी भी चरण में उठाया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा परीक्षण पूर्ण होने के बाद सजा को निरस्त करने और यहां तक कि स्वीकृति की अवैधता के आधार पर पूरी कार्यवाही को रद्द करने के उदाहरण हैं, जैसे कि जमानत आवेदन दाखिल करने से पहले। इस दलील को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न निर्णयों का संदर्भ दिया गया है। ***अशरफ खान बनाम राज्य गुजरात11, राज्य गुजरात बनाम अनवर उस्मान***

सुम्भानिया12, अनिरुद्धसिंहजी करनसिंहजी जडेजा बनाम राज्य गुजरात13, रामभाई नाथाभाई गढवी बनाम राज्य गुजरात14, सीनी नैनार मोहम्मद बनाम राज्य15, और *जमीरुद्दीन अंसारी बनाम सीबीआई16* के मामले उद्धृत किए गए।

8.4 दोनों प्राधिकृत और स्वीकृति देने वाली संस्थाओं ने यह विचार नहीं किया कि मानसिक दोष (आपराधिक मनोवृत्ति) अनुपस्थित है, जो जैसा कि स्थापित है, किसी अपराध की संरचना के लिए आवश्यक होता है, जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से बाहर न रखा गया हो। *पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ17* और *संजय दत्त बनाम राज्य (सीबीआई)18* के मामलों का संदर्भ दिया गया। बाद के निर्णय में यह विचार किया गया था कि यदि एक उचित व्याख्या मौजूद हो जो दंड से बचने की अनुमति देती है, तो न्यायालयों को उस दृष्टिकोण को अपनाने का आदेश दिया गया है।

8.5 अपीलकर्ता को पहले मॉड्यूल में (यानी, एफआइआर संख्या 67/2016) और न ही दूसरे मॉड्यूल (जो 22 मई 2018 को कथित हवाला लेन-देन से शुरू हुआ था) में आरोपी नहीं बनाया गया था, और इसके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 2019 को स्वीकृति दी गई थी। वास्तव में, उसे ए-20 के साथ एक स्वतंत्र लेन-देन में आरोपी बनाया गया, जिसके संबंध में स्वीकृति आदेश (जो यहां चुनौतीपूर्ण है) 22 जुलाई, 2020 को जारी किया गया था।

8.6 धारा 22ए की उपधारा एक व्यक्ति को अभियोजन से छूट देती है, जो कंपनी के मामलों का प्रभार और जिम्मेदारी नहीं रखता। अपीलकर्ता का तर्क है कि उसे गलत तरीके से कार्यवाही में घसीटा गया है, जबकि वह एक मुंशी है जो दैनिक वेतन पर काम करता है। वह निरक्षर है और व्यापारिक लेन-देन को समझता नहीं है। ए-6 ने उसकी स्थिति का अनुचित लाभ उठाया, जब ए-7 और ए-14 ने उसकी पहचान चुरा ली।

---

11 [2012] 12 एससीआर1033 : (2012) 11 एससीसी 606

12 [2019] 2 एससीआर 749 : (2019) 18 एससीसी 524

13 [1995] सप. 2 एससीआर 637: (1995) 5 एससीसी 302

14 [1997] सप. 3 एससीआर 356: (1997) 7 एससीसी 744

15 [2017] 3 एससीआर 312: (2017) 13 एससीसी 685

16 [2009] 7 एससीआर 759: (2009) 6 एससीसी 316

17 [2004] 1 एससीआर 232 : (2004) 9 एससीसी 580
18 [1994] सप. 3 एससीआर 263 : (1994) 5 एससीसी 410

8.7 अपीलकर्ता को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है। एनआईए ने इस मामले को उस पर लाद दिया है, क्योंकि (अ) वह कंपनी ए-20 में निदेशक है; (ब) उस कंपनी को कथित रूप से ऐसे फंड मिले थे जिन्हें पीएलएफआइ द्वारा उपयोग किया जाना था; (स) वह उसी स्थान का निवासी है और दिनेश गोप से जो पीएलएफआइ का नेता है, एक दूर का परिचित है।

9. उत्तरदाता भारत सरकार का रुख -, जैसा कि अभिलेख पर मौजूद सामग्री और लिखित प्रस्तुतियों से समझा जा सकता है, यह है कि –

9.1 यह कहा गया है कि वर्तमान कार्यवाही की शुरुआत में जो स्वीकृति आदेश दिया गया है, वह उचित प्रक्रिया का पालन करके जारी किया गया है। एनआईए ने 14 जुलाई 2020 को अपने पत्र के माध्यम से आरोपियों सहित वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन की सिफारिश की। केंद्रीय सरकार ने, यूएपीए की धारा 45(2) के अनुसार, 15 जुलाई 2020 को दो सदस्यीय प्राधिकरण के पास जांच रिपोर्ट भेजी, ताकि स्वतंत्र समीक्षा की जा सके। प्राधिकरण ने 16 जुलाई 2020 को अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को समय सीमा के भीतर भेज दी, जो 2008 नियमों के तहत निर्धारित है। अन्य शब्दों में, नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

9.2 चुनौतीपूर्ण स्वीकृति आदेश को सभी संबंधित सामग्री को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है, जिसमें यूएपीए की धारा 45(2) के तहत गठित प्राधिकरण की सिफारिश भी शामिल है। प्राधिकरण में एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायधीश और एक सेवानिवृत्त कानून सचिव थे।

9.3 स्वतंत्र समीक्षा सभी संबंधित चरणों में की गई, जिसके बाद केंद्रीय सरकार ने स्वीकृति दी। केवल इस कारण कि सिफारिश के एक दिन के भीतर स्वीकृति दी गई, यह नहीं कहा जा सकता कि मनन नहीं किया गया था।

9.4 दूसरे और तीसरे मॉड्यूल, जैसा कि अनुपूरक आरोप पत्रों में समझाया गया है, एफआइआर में शुरू हुए लेन-देन से स्वतंत्र और अलग लेन-देन नहीं हैं, बल्कि ये वही निरंतर लेन-देन का

हिस्सा हैं, जिसे आरोपियों ने आतंकवाद से प्राप्त धन को चैनलाइज करने के लिए किया था। एनआईए ने जांच का जिम्मा लिया और दो अनुपूरक आरोप पत्र दाखिल किए।

9.5 अपीलकर्ता एक आतंकवादी गिरोह का सक्रिय सदस्य है और दिनेश गोप (ए-6) का करीबी सहयोगी है, और उसने कंपनियां बनाकर धन एकत्रित करने और उसे चैनलाइज करने में भाग लिया। ए-20, जिसमें अपीलकर्ता/ए-17 निदेशक था, आतंकवाद से प्राप्त धन को मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए एक मोर्चा था। अपीलकर्ता का यह दावा कि ए-7 और ए-14 ने उसकी पहचान चुराई, निराधार है और ऐसी अस्पष्ट याचिका पर कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता।

9.6 ट्रायल बहुत ही उन्नत चरण में है, और इसलिए, आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में कोई विवेक नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए।

10. सर्वप्रथम, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि, हालांकि माननीय अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा की गई अंतिम प्रस्तुतियों के बावजूद, अपीलकर्ता ने अपनी प्रस्तुतियों पर निर्णय के लिए निष्कर्ष प्राप्त करने का आग्रह किया। इसलिए, हम इस मामले को योग्यता पर निर्णय देने के लिए आगे बढ़ते हैं।

<u>इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न इस प्रकार हैं:</u>

11. वास्तविक परिस्थितियों और पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, हमारे विचारणीय निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैं-:

(i) क्या अनुमति आदेश की वैधता को किसी भी चरण में चुनौती दी जा सकती है?

(ii) क्या यूएपीए की धारा 45(2) और नियम 3 और 4 के उल्लंघन से कार्यवाही प्रभावित होती है? दूसरे शब्दों में, क्या - (अ) वैधानिक समयसीमाओं का उल्लंघन और (ब) स्वतंत्र समीक्षा की आवश्यकता, जिसमें मनन का अनुप्रयोग भी शामिल है, एक आवश्यक प्रक्रिया पहलू है, जिसके बिना यूएपीए के तहत कोई भी लेन-देन इस हद तक समझौता कर दिया जाएगा कि उसकी पवित्रता संदिग्ध हो जाएगी?

(iii) क्या वर्तमान तथ्यों में अपीलकर्ता का यह तर्क कि जिन लेन-देन के संबंध में उसे आरोपित किया गया है, वे वास्तव में उन लेन-देन से स्वतंत्र थे, जिनमें दिनेश गोप (ए-6) और अन्य सदस्य आरोपी थे, कोई सार्थकता रखता है?

(iv) क्या, इन तथ्यों में, यूएपीए की धारा 22ए के तहत वैधानिक छूट अपीलकर्ता पर लागू होती है जो कंपनी के मामलों से अनजान होने का दावा करता है?

<u>विचार</u>

<u>एक परिचय :यूएपीए</u>

12. अधिनियम की प्रस्तावना इस प्रकार है:-
"एक अधिनियम जो व्यक्तियों और संगठनों की कुछ अवैध गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम के लिए प्रदान करता है], और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए,] और इससे संबंधित मामलों के लिए।"

13. इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने (जिसमें हम दोनों सदस्य थे) ***<u>अरूप भुइयाँ बनाम असम राज्य</u>***[19] मामले में अधिनियम के उद्देश्य पर निम्नलिखित शब्दों में विचार किया।

"85. यूएपीए का मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियाँ प्रदान करना है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रीय एकता परिषद के तहत नियुक्त समिति की सिफारिश पर संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 को पारित किया गया, जिसके आधार पर यूएपीए को अधिनियमित किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय एकता परिषद ने राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीयकरण पर एक समिति नियुक्त की थी, जो मुख्य रूप से संप्रभुता और अखंडता के हित में उचित अनुमति लगाने के पहलू को देख रही थी और उसके बाद यूएपीए को अधिनियमित किया गया। इसलिए, यूएपीए को भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियाँ प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया।

---

19. [2023] 8 एससीआर 496 : (2023) 8 एससीसी 745

86. अब हम यूएपीए, 1967 के प्रस्तावना पर विचार करें। प्रस्तावना के अनुसार, यूएपीए को व्यक्तियों और संगठनों की कुछ अवैध गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से रोकने और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए और संबंधित मामलों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है। इसलिएयूएपीए के अधिनियमन का उद्देश्य और उद्देश्य यह भी है कि कुछ अवैध गतिविधियों को अधिक प्रभावी तरीके से रोका जा सके। यही कारण है कि और उक्त उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसद ने यह प्रावधान किया कि यदि किसी

संगठन को धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा अवैध घोषित किया जाता है, तो एक व्यक्ति, जो उस संगठन का सदस्य है और बना रहता है, उसे 2 वर्षों तक की सजा दी जा सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए संसद ने अपनी समझ में यह उचित समझा कि जब एक संगठन को धारा 3 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अवैध घोषित कर दिया जाता है और न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो भी यदि कोई व्यक्ति उस संगठन का सदस्य बना रहता है, तो उसे दंडित/सजा दी जा सकती है।"

(विशेष रूप से जोर दिया गया)

(ब) संबंधित कानूनी प्रावधान

14. इस महत्वपूर्ण समय पर हम लागू कानून और नियमों का संदर्भ देंगे।

14.1 धारा 2 (कानून की परिभाषा धारा-:की आवश्यक उपधाराएँ निम्नलिखित हैं (

"2. परिभाषाएँ.-(1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ अन्यथा न निर्धारित करे,-

... ...

(ई) "नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी" का मतलब केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी से है, जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो, या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी से है, जो सचिव के पद से

नीचे का न हो, जैसा कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट किया गया हो;

... ...

(ईसी) "व्यक्ति" में निम्नलिखित शामिल हैं— (i) एक व्यक्ति, (ii) एक कंपनी, (iii) एक फर्म, (iv) एक संगठन या व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का समूह, चाहे वह निगमित हो या नहीं, (v) हर कृत्रिम कानूनी व्यक्ति, जो उपरोक्त में से किसी भी उपधारा के तहत न आता हो, और (vi) कोई भी एजेंसी, कार्यालय या शाखा, जो किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित या स्वामित्व वाली हो, जो उपरोक्त में से किसी भी उपधारा के तहत आता हो;

(एफ) "निर्धारित" का मतलब इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित है;

... ...

(ग) "आतंकवाद से प्राप्त धन" का मतलब है,— (i) सभी प्रकार की संपत्ति, जो किसी आतंकवादी कृत्य के पालन या उससे प्राप्त की गई हो या जो आतंकवादी कृत्य से जुड़ी धनराशियों के माध्यम से अर्जित की गई हो, चाहे उस संपत्ति के नाम पर हो या जिस व्यक्ति के पास वह पाई जाती है; या (ii) कोई संपत्ति जो किसी आतंकवादी कृत्य के लिए या किसी व्यक्तिगत आतंकवादी या आतंकवादी गिरोह या आतंकवादी संगठन के उद्देश्य के लिए उपयोग की जा रही हो या उपयोग में लाने का इरादा हो। स्पष्टीकरण.—इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए, यह घोषित किया जाता है कि "आतंकवाद से प्राप्त धन" शब्द में ऐसी कोई भी संपत्ति शामिल है जो आतंकवाद के लिए उपयोग करने का इरादा रखती हो;"

14.2 अधिनियम की धारा 45 को संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है।

"45. अपराधों का संज्ञान.— [(1)] कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा—

(i) <u>अध्याय III के अंतर्गत बिना केंद्रीय सरकार या की ओर से अधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व अनुमति के</u>;

(ii) अध्याय IV और VI के अंतर्गत बिना केंद्रीय सरकार या, जैसा कि मामला हो, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के, और यदि ऐसा अपराध किसी विदेशी देश की सरकार के खिलाफ किया गया हो, तो बिना केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के।

(2) उपधारा (1) के तहत अभियोजन के लिए अनुमति केवल ऐसे समय में दी जाएगी जैसा कि निर्धारित किया गया हो, केवल उस प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद जिसे केंद्रीय सरकार या, जैसा कि मामला हो, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, जो जांच के दौरान एक स्वतंत्र समीक्षा करेगा और एक सिफारिश करेगा, जो कि निर्धारित समय के भीतर केंद्रीय सरकार या, जैसा कि मामला हो, राज्य सरकार को भेजी जाएगी।"

(जोर दिया गया)

14.3 2008 नियमों की धारा 3 और 4 इस प्रकार पढ़ी जाती हैं:

"3. **प्राधिकरण द्वारा सिफारिश करने की समय सीमा** – प्राधिकरण, धारा 45 की उपधारा (2) के तहत, केंद्रीय सरकार [या, जैसा कि मामला हो, राज्य सरकार] को जांच अधिकारी द्वारा संहिता के तहत एकत्र किए गए साक्ष्य प्राप्त करने के सात कार्य दिवसों के भीतर अपनी रिपोर्ट जिसमें सिफारिशें होंगी, प्रस्तुत करेगा।"

"4. **अभियोजन की स्वीकृति की समय सीमा**या] केंद्रीय सरकार - , जैसा कि मामला हो, राज्य सरकार धारा 45 की उपधारा)2) के तहत, प्राधिकरण की सिफारिशों की प्राप्ति के सात कार्य दिवसों के भीतर अभियोजन की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लेगी।"

(जोर दिया गया)

<u>प्रश्न 1 - अनुमति की वैधता पर चुनौती किस चरण में -?</u>

15. अब, हम इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत पहले प्रश्न की जांच करेंगे। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम अनुमति आदेश के संबंधित हिस्से को उद्धृत करें:

"5. और जबकि, केंद्रीय सरकार ने अनलॉफ़ुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 1967 (जैसा कि संशोधित है) की धारा 45(2) और अनलॉफ़ुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) (सिफारिश और अभियोजन की अनुमति) नियम 2008 के प्रावधानों के अनुसार, उपरोक्त उल्लेखित जांच रिपोर्ट को 15 जुलाई, 2020 के इस मंत्रालय के पत्र के माध्यम से प्राधिकरण के पास भेजा, जिसमें दो सदस्य थे - न्यायमूर्ति डॉ. सत्यश चंद्र (सेवानिवृत्त) और डॉ. टीके विश्वनाथन, कानून सचिव (सेवानिवृत्त),

जिन्हें इस मंत्रालय के आदेश संख्या 11034/1/2009/IS-IV दिनांक 03.07.2015 द्वारा स्वतंत्र समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था (प्राधिकरण का कार्यकाल 12.06.2020 के इस मंत्रालय के आदेश द्वारा 31.07.2021 तक बढ़ाया गया था);

6. और जबकि, प्राधिकरण ने 16 जुलाई, 2020 के पत्र के माध्यम से अपनी रिपोर्ट इस मंत्रालय को निर्धारित समय सीमा के भीतर भेज दी, जैसा कि अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) (सिफारिश और अभियोजन की अनुमति) नियम 2008 में निर्धारित किया गया है और, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और तथ्यों और परिस्थितियों से संतुष्ट होकर, अभियुक्तों/संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन की अनुमति की सिफारिश की, जो कानून की संबंधित धाराओं के तहत अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 1967 सहित हैं;

7. और अब, इसलिए, केंद्रीय सरकार, रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री और प्राधिकरण की सिफारिशों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, यह संतुष्ट है कि अभियुक्तों/संस्थाओं के खिलाफ संबंधित कानून की धाराओं के तहत एक प्राइमा फेसि मामला बनता है और इस प्रकार धारा 45(1) के तहत अभियोजन की अनुमति प्रदान करती है।"

आदेश द्वारा और भारत के

राष्ट्रपति के नाम पर

हस्ताक्षरित /-

(धर्मेंद्र कुमार)

भारत सरकार के अधीन सचिव"

(जोर दिया गया)

16. स्वीकृति की वैधता को चुनौती देने और इसे किस चरण में अनुमति दी जा सकती है, इस प्रश्न ने इस न्यायालय को कुछ पिछले अवसरों पर व्यस्त रखा है, हालांकि यह अलग-अलग विधियों के संदर्भ में था। इनका उल्लेख करना उपयोगी होगा।

16.1 ***केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम अशोक कुमार अग्रवाल***[20] मामले में, इस न्यायालय ने स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया के महत्व को नोट किया। इसे "कठोर प्रक्रिया नहीं बल्कि एक गंभीर और पवित्र कार्य" कहा गया है, विशेष रूप से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम[21], 1988 के संदर्भ में।

न्यायालय ने अभियोजन की वैधता के लिए आवश्यक तत्वों को निम्नलिखित रूप में संक्षेप में प्रस्तुत किया:-

"16. उपरोक्त के दृष्टिगत, विधिक प्रस्तावों को निम्नलिखित रूप में संक्षेप किया जा सकता है:

16.1 अभियोजन को स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकरण को सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड भेजने चाहिए, जिनमें एफआईआर, खुलासा बयान, गवाहों के बयान, बरामदगी मेमो, ड्राफ्ट चार्जशीट और अन्य सभी संबंधित सामग्री शामिल हो। इन रिकॉर्ड्स में वह सामग्री/दस्तावेज भी शामिल होना चाहिए, जो आरोपी के पक्ष में हो सकते हैं और जिनके आधार पर सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है।

16.2 प्राधिकरण को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत पूरे रिकॉर्ड की पूर्ण और सचेत जांच स्वयं करनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से अपनी सोच लागू करनी चाहिए और स्वीकृति प्रदान करने से पहले सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करना चाहिए। यह निर्णय देते समय उसे स्वीकृति देने या न देने की अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

16.3 स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति का उपयोग सख्ती से सार्वजनिक हित और उस आरोपी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, जिसके खिलाफ स्वीकृति मांगी गई है।

16.4 स्वीकृति का आदेश यह स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए कि प्राधिकरण सभी प्रासंगिक तथ्यों/सामग्रियों से अवगत था और उसने उन पर अपनी सोच लागू की थी।

16.5 प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में अभियोजन को यह स्थापित करना और न्यायालय को यह संतुष्ट करना होगा कि सभी प्रासंगिक तथ्य स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकरण के सामने प्रस्तुत किए गए थे, प्राधिकरण ने उन पर विचार किया था, और स्वीकृति कानून के अनुसार प्रदान की गई थी।

(जोर दिया गया)

---

20 [2013] 14 एससीआर 983 : (2014) 14एससीसी 295

21 आगे 'पीसी अधिनियम' के रूप में संदर्भित।'

16.2 *प्रकाश सिंह बादल बनाम पंजाब राज्य22* के मामले में, इस न्यायालय ने यह माना कि स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकरण प्रत्येक अपराध को, जो आरोपी लोक सेवक के खिलाफ है, अलग से निर्दिष्ट करने के लिए बाध्य नहीं है। यह कार्य आरोप तय करने के चरण में किया जाना चाहिए। कानून की अपेक्षा यह है कि स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकरण के समक्ष ऐसी सामग्री प्रस्तुत की जाए, जिससे वह निर्णय लेने के लिए अपने मस्तिष्क का उपयोग कर सके।

16.3 *दिनेश कुमार बनाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया23* के मामले में, न्यायमूर्ति लोढ़ा (तत्कालीन न्यायाधीश) ने यह टिप्पणी की:

"10. हमारे विचार में, जब स्वीकृति का आदेश मौजूद हो, तब भी स्वीकृति की अमान्यता विभिन्न आधारों पर उठाई जा सकती है, जैसे स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकरण के समक्ष सामग्री की अनुपलब्धता, प्राधिकरण का पक्षपात, या स्वीकृति आदेश का किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा पारित किया जाना। ये आधार केवल उदाहरणात्मक हैं, न कि पूर्ण। स्वीकृति की अमान्यता या अवैधता के सभी ऐसे आधार उसी श्रेणी में आएंगे, जैसे स्वीकृति की अमान्यता के लिए मस्तिष्क का प्रयोग न करना—एक श्रेणी जिसे इस न्यायालय ने **प्रकाश सिंह बादल** [(2007) 1 एससीसी 1 : (2007) 1 एससीसी (आपराधिक) 193] मामले में स्थापित किया था। इस प्रकार की चुनौती को हमेशा मुकदमे के दौरान उठाया जा सकता है।"

16.4 **सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अन्य बनाम प्रमिला वीरेंद्र कुमार अग्रवाल24** के मामले में, इस न्यायालय ने दिनेश कुमार (उपर्युक्त) का संदर्भ लेते हुए स्वीकृति के अभाव और स्वीकृति की कथित अमान्यता (मस्तिष्क के प्रयोग न करने के कारण) के बीच के अंतर को दोहराया। न्यायालय ने माना कि स्वीकृति के अभाव का मुद्दा प्रारंभिक चरण में उठाया जा सकता है, जबकि अमान्यता का मुद्दा केवल मुकदमे के दौरान ही उठाया जा सकता है।

16.5 तीन न्यायाधीशों की पीठ ने *पी.के. प्रधान बनाम सिक्किम राज्य25* के मामले में *दंड प्रक्रिया संहिता, 1973* की धारा 197 के लागू होने पर चर्चा की। विभिन्न पूर्व निर्णयों का संदर्भ लेते हुए, उन्होंने निष्कर्ष निकाला:

"15. …यह अच्छी तरह से स्थापित है कि धारा 197 के तहत स्वीकृति का प्रश्न कभी भी उठाया जा सकता है—जैसे कि संज्ञान लेने के तुरंत बाद, आरोप तय होने के बाद, या यहां तक कि मुकदमे की समाप्ति और दोषसिद्धि के बाद भी। लेकिन कुछ मामलों में यह संभव नहीं हो सकता कि बिना प्रतिरक्षा को यह अवसर दिए कि वह यह साबित कर सके कि उसने जो भी कार्य किया, वह उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किया गया था, इस प्रश्न को प्रभावी ढंग से

तय किया जा सके। यह निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि आरोपी का यह दावा कि जो कार्य उसने किया वह उसके कर्तव्य के प्रदर्शन के दौरान किया गया था और यह दावा न तो दिखावा था और न ही काल्पनिक, मुकदमे के दौरान जांच की जा सकती है और प्रतिरक्षा को इसे स्थापित करने का अवसर दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में, स्वीकृति का प्रश्न मुख्य निर्णय में छोड़ा जा सकता है, जो मुकदमे के समापन के बाद दिया जाएगा।"

(जोर दिया गया)

16.6 हाल ही में, इस न्यायालय ने ***कर्नाटक राज्य बनाम एस. सुब्बेगौड़ा***[27] के मामले में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संदर्भ में स्वीकृति और उसकी वैधता के प्रश्न पर चर्चा की। न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि स्वीकृति को चुनौती प्रारंभिक चरण में ही उठाई जानी चाहिए और यह माना:

"10. … यह विधि का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि स्वीकृति की वैधता से संबंधित प्रश्न कार्यवाही के प्रारंभिक चरण में उठाया जाना चाहिए, हालांकि इसे मुकदमे के बाद के चरण में भी उठाया जा सकता है। हमारे विचार में, कार्यवाही के वे चरण जिनमें आरोपी स्वीकृति की वैधता के मुद्दे को उठा सकता है, वे हैं: जब न्यायालय अपराध का संज्ञान लेता है, जब न्यायालय आरोप तय करने वाला होता है, या जब मुकदमा पूरा हो चुका होता है, अर्थात मुकदमे में अंतिम तर्कों के चरण में। निस्संदेह, इस मुद्दे को अपील, पुनरावलोकन, या पुष्टि के दौरान भी न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है। हालांकि, ऐसे न्यायालय की शक्तियां धारा 19 के उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के अधीन होंगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि आरोपी की सुनवाई करने वाले न्यायालय की अधिकारिता स्वीकृति की वैधता के अस्तित्व पर निर्भर करती है। इसलिए, यह हमेशा वांछनीय है कि स्वीकृति की वैधता का प्रश्न सबसे पहले उठाया जाए। यह कहा नहीं जा सकता कि यदि स्वीकृति अमान्य पाई जाती है, तो परीक्षण न्यायालय आरोपी को बरी कर सकता है और पक्षों को उस चरण पर वापस भेज सकता है, जहां सक्षम प्राधिकरण अभियोजन के लिए

---

22 [2006] सप. 10 एससीआर 197 : (2007) 1 एससीसी 1

23 [2011] 13 एससीआर 260 : (2012) 1 एससीसी 532

24 (2020) 17 एससीसी 664

25 [2001] 3 एससीआर 1119 : (2001) 6 एससीसी 704

26 आगे 'सीआरपीसी' के रूप में संदर्भित

27 [2023] 11एससीआर 19 : 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 911

कानून के अनुसार नई स्वीकृति प्रदान कर सकता है।"

(जोर दिया गया)

17. उपरोक्त उद्धृत प्राधिकरण केवल एक निष्कर्ष की ओर संकेत करते हैं, जो यह है कि स्वीकृति को, हालांकि इसे पहले अवसर पर चुनौती दी जानी चाहिए, बाद के चरण में भी चुनौती दी जा सकती है। ये निर्णय, हालांकि विशेष रूप से ऐसे कानूनों के संदर्भ में नहीं हैं जैसे कि यूएपीए , एक सामान्य रूप से स्वीकार्य नियम प्रस्तुत करते हैं कि आरोपी को उपलब्ध अधिकार, जो उसकी निर्दोषता स्थापित करने का अवसर प्रदान कर सकता है, कानून द्वारा समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि विशेष रूप से कानूनी पाठ्य में ऐसा प्रावधान न हो। साथ ही, स्वीकृति की वैधता को चुनौती देना न तो और न ही ऐसा एक उपकरण होना चाहिए जिससे वैध अभियोजन को धीमा या अवरुद्ध किया जा सके। अन्य विधान जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता ऐसे तंत्र प्रदान करते हैं जिससे स्वीकृति और इसके बाद की क्रियाओं को किसी भी असमानता आदि के कारण अमान्य होने से बचाया जा सकता है। धारा 465 दंड प्रक्रिया संहिता यह संभावना प्रदान करती है कि धारा 197 दंड प्रक्रिया संहिताके तहत दी गई
स्वीकृति को उसकी कार्यवाही द्वारा बचाया जा सकता है। इसी तरह, यदि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दी गई स्वीकृति में कोई त्रुटि, चूक या असमानता पाई जाती है, तो उसे न्याय की विफलता का कारण नहीं बनने तक अमान्य नहीं किया जाएगा।

18. यूएपीए में स्वीकृति को बचाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब यह है कि, विधायिका के विवेक में, इस अधिनियम का अंतर्निहित तंत्र जिसमें दो प्राधिकरण स्वीकृति देने से पहले अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हैं, यह पर्याप्त है। यह दोनों प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले कार्य की भूमिका और पवित्रता को रेखांकित करता है। स्वीकृति को अमान्य मानकर चुनौती देने के लिए जो आधार पेश किए जा सकते हैं, वे हैं: (1) सभी संबंधित सामग्री प्राधिकरण के समक्ष नहीं रखी गई; (2) प्राधिकरण ने उक्त सामग्री पर अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया; और (3) सामग्री की अपर्याप्तता। यह सूची केवल उदाहरणात्मक है और पूरी नहीं है। चुनौती के तीनों आधारों में एक सामान्य धागा यह है कि इस चुनौती को प्रस्तुत करने वाली पार्टी को इस प्रभाव को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। यह, बिना कहे, केवल मुकदमे की अदालत के समक्ष ही किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से, हमें कोई संकोच नहीं है कि हम यह मानते हुए कि हम आरोपी के द्वारा कानून के तहत उपलब्ध सभी उपायों का उपयोग करने के अधिकार को स्वीकार करते हैं, सामान्य परिस्थितियों में यूएपीए के तहत स्वीकृति की चुनौती को संभवतः पहले अवसर पर उठाया जाना चाहिए, ताकि मुकदमे की अदालत इस प्रश्न को तय कर सके,

क्योंकि इस पर निर्भर करेगा कि क्या वह आगे की कार्रवाई कर सकती है और कोई अन्य अपील पक्ष की कार्रवाई इस प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करेगी। [देखें: एस. सुब्बेगौड़ा (उपर्युक्त)]

वर्तमान मामले के संदर्भ में, यह ध्यान में रखते हुए कि बार में यह प्रस्तुत किया गया कि मुकदमा चल रहा है और कई गवाहों (125 में से 113) की पहले ही जांच हो चुकी है, हम इस मामले में स्वीकृति की वैधता को चुनौती देने पर कोई निर्णय देने से बचते हैं और इसे मुकदमे के न्यायधीश के समक्ष उठाने के लिए छोड़ते हैं, जो यदि इस प्रश्न को उठाया जाता है तो इसे शीघ्रता से निपटाएंगे।

<u>मुद्दा संख्या 2:</u>

19. अगला मुद्दा जिसे हमें विचार करना है, वह यह है कि क्या यूएपीए की धारा 45(2) और 2008 के नियमों की धारा 3 और 4 के अनुसार समयसीमा और स्वतंत्र समीक्षा की आवश्यकता प्रक्रिया के आवश्यक पहलू हैं, जिनका पालन न करने से कार्यवाही प्रभावित हो सकती है। जैसा कि ऊपर पहले ही उद्धृत किया गया है, नियमों के अनुसार संबंधित प्राधिकरण को जांच अधिकारी द्वारा एकत्रित सामग्री के आधार पर अपनी सिफारिश करने के लिए सात दिन का समय मिलता है, और इसके बाद सरकार को अभियोजन के लिए स्वीकृति देने के लिए सात दिन का अतिरिक्त समय मिलता है, जब उसने प्राधिकरण की रिपोर्ट पर विचार किया हो।

20. अपीलकर्ता का तर्क यह है कि उक्त समयसीमा का पालन नहीं किया गया और वास्तव में, पहले की स्वीकृति सिफारिश के एक साल बाद दी गई। यह तर्क एक और दावे से जुड़ा है, कि सिफारिश करने वाली प्राधिकरण और केंद्रीय सरकार द्वारा कोई स्वतंत्र समीक्षा नहीं की गई, क्योंकि स्वीकृति केवल एक दिन में दी गई।

<u>समयसीमा, क्या यह निर्देशात्मक हैं या अनिवार्य?</u>

21. अब हम अपीलकर्ताओं के एक प्रमुख तर्क पर विचार करें, अर्थात् कानूनी समयसीमाओं का पालन न करना।

22. सामान्य रूप से, कानूनी ढांचे के तहत समयसीमाएं अपराध की जांच, अभियोजन और मुकदमे की प्रभावी, कुशल और लक्षित मशीनरी के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यह कहा जा सकता है कि कानून की इन प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन में सभी संबंधित पक्षों को इन समयसीमाओं को पूरा करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ये समयसीमाएं जल्दी सुनवाई का अधिकार के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सुनिश्चित किया गया है।

23. अपीलकर्ताओं की समयसीमाओं के बारे में आपत्तियां दो प्रमुख बिंदुओं पर आधारित हैं। पहली, यह कि पहले की स्वीकृति और उनकी गिरफ्तारी के बीच एक बड़ा अंतर है, यह मानते हुए कि वे अभियुक्त के अनुसार उसी निरंतर लेन-देन का हिस्सा हैं, और दूसरी, यह कि प्राधिकरण को जांच अधिकारियों द्वारा एकत्रित सामग्री पर विचार करने और सिफारिश करने के लिए सात दिन का समय दिया गया था, फिर भी उन्होंने यह काम एक दिन के भीतर किया, और वह भी एक ऐसे तरीके से जो यांत्रिक कहा जा सकता है, जिससे सिफारिशों में मस्तिष्क के न प्रयोग होने का दोष लगता है।

24. पहली आपत्ति हमें अधिकतम सतही प्रतीत होती है। इस आपत्ति को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियों का उल्लेख किया जाना चाहिए:

क्रम संख्या	**विवरण**	**तिथि**
1.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	10 नवंबर 2016
2.	आरोपपत्र (यह नोट किया गया कि ए-6 के खिलाफ जांच जारी है(	9 जनवरी 2017
3.	ए-6 के खिलाफ अनुमति	16 अक्टूबर 2019
4.	पहला अनुपूरक आरोपपत्र (ए-6 का नाम इसमें है; ए-17 अभियोजन गवाह के रूप में लाया गया है; जांच अभी भी जारी है(	21 अक्टूबर 2019
5.	ए-17 की गिरफ्तारी	13 जुलाई 2020
6.	ए-17 के खिलाफ अनुमति	22 जुलाई 2020
7.	दूसरा अनुपूरक आरोपपत्र (ए-17 का नाम इसमें है(	23 जुलाई 2020

ए-6 के खिलाफ पहली कार्रवाई और अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के बीच का अंतर निरंतर जांच का परिणाम है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को दूसरे अनुपूरक आरोपपत्र में आरोपी के रूप में नामित किया गया, जो उसी एफआइआर से उत्पन्न हुआ था जिसके तहत ए-6

को प्रारंभ में आरोपी बनाया गया था। चूंकि जांच जारी रही, इसलिए इस अंतर को दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता है जिससे अपीलकर्ता की गिरफ्तारी को अवैध या गैरकानूनी माना जा सके। यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि पहले अनुपूरक आरोपपत्र में अपीलकर्ता प्रारंभ में अभियोजन के गवाह के रूप में था और आगे की जांच के बाद उसे आरोपी बनाया गया।

25. दूसरी आपत्ति की merits पर विचार करने के लिए, "मस्तिष्क का प्रयोग" की अवधारणा को समझना जरूरी है। यह कानून में स्थापित है कि मन का प्रयोग किसी भी न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक आदेश का हिस्सा होना चाहिए। इसे स्पष्ट करने के लिए, उस प्राधिकरण के सामने रखे गए सामग्री पर विचार करना अनिवार्य है। साथ ही, यह एक मानसिक प्रक्रिया है, इसलिए यह तर्कसंगत नहीं है कि किसी निश्चित सूत्र के जरिए यह समझाया जाए कि मन का प्रयोग वास्तव में क्या होता है या किस रूप में दिखाई देता है। इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जाना जाना चाहिए।

26. दंडात्मक कानूनों के संदर्भ में, जिन प्राधिकरणों को अभियोजन की स्वीकृति देने से पहले सामग्री का मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा जाता है, या स्वयं स्वीकृति देने का कार्य, उन्हें उस सामग्री के हर पहलू पर विचार करना चाहिए ताकि वे निष्कर्ष पर पहुंच सकें, खासकर इस कारण से कि इस कार्य का प्रभाव विशाल है। स्वीकृति देने या न देने का निर्णय वह पहला कदम होता है जो कड़े कानूनों जैसे यूएपीए या आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधियों (निवारण) अधिनियम28, 1987 को लागू करता है। इन कानूनों की कठोरता और उनसे जुड़े हुए गतिविधियों की प्रकृति को देखते हुए, इनका प्रभाव केवल कानून के दायरे में नहीं बल्कि व्यक्ति के सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए, जब तक प्राधिकरण इस कार्य को सौंपे जाने के बाद यह नहीं मानता कि स्वीकृति दी जा सकती है, तब तक उसे स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।

27. ऐसी विधियों में स्वीकृतियों से संबंधित प्रक्रियाएं कड़ाई से पालन करने के लिए होती हैं, शब्द के मामले में ही नहीं, बल्कि भावना के मामले में भी। लिखित शब्द से सबसे छोटी भिन्नता भी इससे उत्पन्न होने वाली कार्यवाही को संदेहास्पद बना सकती है। जब कोई प्रावधान नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, तो इस सामान्य सिद्धांत को इस न्यायालय ने ***रंगकु दत्ता बनाम असम29*** में निम्नलिखित शब्दों में देखा है:

“18. यह स्पष्ट है कि धारा 20-ए(1) एक कानूनी आवश्यकता है। सबसे पहले, यह एक सर्वोपरि धारा से शुरू होती है और इसके बाद इसके अनिवार्य स्वभाव को रेखांकित करने के लिए "नहीं" शब्द का उपयोग किया जाता है। जब किसी कानून का उद्देश्य अनिवार्य होता है, तो उसे

नकारात्मक आदेश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस संदर्भ में जी.पी. सिंह की "प्रिंसिपल्स ऑफ़ स्टैटूटोरी इंटरप्रिटेशन" (12वीं संस्करण) के पृष्ठ 404-05 पर उल्लिखित टिप्पणी का उल्लेख किया जा सकता है।"

"… जैसा कि क्रॉफर्ड ने कहा: 'निषेधात्मक या नकारात्मक शब्द शायद कभी भी निर्देशात्मक नहीं हो सकते। और यह तब भी लागू होता है जब कानून उल्लंघन के लिए कोई दंड प्रदान नहीं करता।' जैसा कि सुबराव, ज. ने कहा: 'नकारात्मक शब्द स्पष्ट रूप से निषेधात्मक होते हैं और सामान्यतः इन्हें एक विधायी उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि किसी कानून को अनिवार्य बनाया जा सके।' नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 और धारा 87-बी; रेलवे अधिनियम, 1890 की धारा 77; बंबई किराया अधिनियम, 1947 की धारा 15; विरासत अधिनियम, 1925 की धारा 213; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5-ए; स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 7; कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 108; खाद्य मिलावट अधिनियम, 1954 की धारा 20(1); वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 55; औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33(2)(बी) की उपविधि (1956 में संशोधित); चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 10-ए (1993 में संशोधित); और इसी प्रकार की अन्य प्रावधानों को अनिवार्य के रूप में व्याख्यायित किया गया है। एक प्रावधान जो 'कम से कम तीन महीने की सूचना' की आवश्यकता करता है, वह भी इसी कारण से अनिवार्य है।"

हम मान्य लेखक द्वारा की गई उपरोक्त कानूनी बयान से पूरी तरह सहमत हैं।

उदाहरण के लिए, टाडा के तहत यह निर्णय लिया गया है कि यदि धारा 20-ए के तहत स्वीकृति देने वाली प्राधिकरण वह नहीं है जिसने स्वीकृति दी थी और इसके बजाय यह उच्च प्राधिकरण था, तो भी यह स्वीकृति अवैध होगी। इस संदर्भ में ***हुसेन घडियाली बनाम राज्य गुजरात***[30] और **राजस्थान राज्य बनाम. मोहिनुद्दीन जमाल अल्वी**[31] मामलों का उल्लेख किया जा सकता है।

---

28 आगे 'टाडा' के रूप में संदर्भित

29 [2011] 8 एससीआर 639 : (2011) 6 एससीसी 358

30 [2014] 9 एससीआर 364 : (2014) 8 एससीसी 425

31 (2016) 12 एससीसी 608

28. अब यूएपीए के तहत स्वीकृति की प्रक्रिया पर ध्यान देते हुए, हमें यह पाते हैं कि न्यायालय को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना संज्ञान नहीं लेना चाहिए, जैसा कि लागू होता है, और ऐसी स्वीकृति केवल तब दी जाएगी जब केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण की रिपोर्ट पर विचार किया गया हो। यह प्राधिकरण एक स्वतंत्र समीक्षा करेगा, एकत्रित किए गए साक्ष्य की जांच करेगा और समयबद्ध तरीके से सरकार को सिफारिश प्रस्तुत करेगा।

28.1 उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि यदि कोई न्यायालय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना संज्ञान लेता है, तो यह अधिनियम का उल्लंघन होगा और इसलिए कानूनी दृष्टि से गलत होगा। यह स्वीकृति केवल सरकार का कार्य नहीं है, और इसे केवल तभी दिया जा सकता है जब एक स्वतंत्र निकाय, हालांकि वह सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, साक्ष्य की स्वतंत्र समीक्षा करता है।

28.2 यह तथ्य कि स्वीकृति दी गई है, विवादित नहीं है। विवादित यह है कि वह स्वीकृति किस प्रकार दी गई। अपीलकर्ता के अनुसार, प्राधिकरण की सिफारिश और तुरंत उसके बाद सरकार द्वारा स्वीकृति देना यह दर्शाता है कि विचार-मंथन की अनुपस्थिति है और आदेशों में समानता या 'साइकलोस्टाइल' तरीके से दिए गए आदेश हैं।

28.3 हालांकि हमने वर्तमान अपील तक पहुँचने वाली परिस्थितियों का अवलोकन किया है, लेकिन तात्कालिक संदर्भ में हम यहाँ यह याद कर सकते हैं कि एनआइए ने अपनी 14 जुलाई 2020 की पत्र के माध्यम से सात व्यक्तियों (ए-13 से ए-20) के खिलाफ अभियोजन की सिफारिश की; मंत्रालय ने 15 जुलाई 2020 को अपनी पत्र में जांच रिपोर्ट प्राधिकरण को भेजी; और प्राधिकरण ने अगले दिन, यानी 16 जुलाई 2020 को इन सात व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी।

28.4 2008 के नियमों के नियम 3 और 4, जो ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए हैं, प्राधिकरण और सरकार को एक सप्ताह का समय देते हैं, ताकि वे सिफारिश कर सकें और फिर स्वीकृति प्रदान कर सकें। पहले दृष्टिकोण से, वर्तमान स्वीकृति निर्धारित समय सीमा के भीतर दी गई है।

हालांकि, जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह तथ्य कि सिफारिश, विचार और स्वीकृति तीन दिनों के भीतर हुई, क्या यह अभियोजन को पूरी तरह से दोषपूर्ण बना देता है?

28.5 दोनों प्राधिकरणों को एक सप्ताह का समय दिया जाता है ताकि वे स्वतंत्र रूप से पहले रिकॉर्ड पर रखे गए सामग्रियों का मूल्यांकन कर सकें और फिर स्वीकृति की सिफारिश कर सकें; और दूसरे, सामग्रियों और उपरोक्त सिफारिश का मूल्यांकन करके, अंत में अनुमति का आदेश जारी कर सकें। यदि दिया गया समय पूरी तरह से अनुपयोगी होता है या यदि इन दोनों में से कोई एक प्राधिकरण समय सीमा से अधिक चला जाता है, जैसा कि नियमों में निर्धारित है, तो उस समय के दौरान जारी की जा रही अनुमति का क्या होगा? इस मुद्दे पर उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। यह कानून का एक स्वीकृत सिद्धांत है कि कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होना चाहिए, जिससे यह संकेत मिलता है कि विभिन्न क्षेत्रों में लागू होने के बावजूद कानून को कैसे लागू किया जाना चाहिए, उसमें एकरूपता होनी चाहिए। भारत की विधि आयोग ने अपनी 136वीं रिपोर्ट में "असमानता" को एक "दुष्टता" के रूप में पहचाना था। इस समस्या को इस प्रकार स्वीकार किया गया है:

"1.2 समानता की चाह एक बुराई- यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि कानून में असमानता न केवल विधिक गुणवत्ता या प्रक्रियात्मक कानून को खराब करती है, बल्कि नागरिकों के लिए गंभीर असुविधा भी उत्पन्न करती है। जो लोग कानून के बारे में सलाह देने का काम करते हैं, उन्हें यह सलाह देना कठिन हो जाता है जब निर्णयों में विरोधाभास होता है। जो लोग कानून पर निर्णय लेने का कार्य करते हैं, उन्हें इस विषय पर विचार करने में समय बिताना पड़ता है, जिस पर दो या अधिक संभावित दृष्टिकोण हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में समय और ऊर्जा की काफी बर्बादी होती है। इसके अलावा, यह एक संतोषजनक स्थिति नहीं है कि एक ही विषय पर देश के एक हिस्से में लागू होने वाला कानून देश के दूसरे हिस्से में लागू होने वाले कानून से अलग हो, जब यह भेदविवाद न्यायिक व्याख्याओं के कारण उत्पन्न हो।"

28.5.1 बंबई उच्च न्यायालय ने (नागपुर पीठ), आपराधिक अपील संख्या 136 और 137 of 2017 में, जो के रूप में प्रसिद्ध है "**महेश करीमन तिर्की बनाम महाराष्ट्र राज्य**", इस न्यायालय द्वारा 19 अप्रैल 2023 को पारित आदेश में, जिसमें एसएलपी संख्या (.क्रिम)11072-11073/2022 पर निर्णय के लिए नवीनीकरण किया गया था, समयसीमाओं के संदर्भ में 2008 नियमों के तहत निम्नलिखित निर्णय दिया:

“153. यद्यपि शब्द "करेगा" निःसंदेह तात्कालिकता का संकेत देता है, लेकिन नियमों में शब्दों से जो परिणाम गैर-अनुपालन से उत्पन्न होते हैं, उन्हें कानून में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। न तो अभियोजन के प्रारंभिक चरण में और न ही हमारे सामने रक्षा पक्ष ने समयसीमा के सख्त अनुपालन से किसी प्रकार के नुकसान की बात रखी है।

154. इस प्रावधान का उद्देश्य यह है कि प्रक्रिया का पालन किया जाए और उसे शीघ्रता से पूरा किया जाए। विशेष रूप से, हमने उस परिदृश्य को ध्यान में रखा है, जो तब उत्पन्न हो सकता है यदि इस संदर्भ में शब्द "करेगा" को अनिवार्य माना जाए। इस स्थिति में, अगर एक दिन की भी देरी हो जाती है, तो यह आतंकवाद के कृत्य को नियंत्रित करने के लिए चलाए जा रहे अभियोजन को रोक सकता है। निश्चित रूप से, "shall" शब्द को इस प्रकार की तात्कालिकता के रूप में शामिल करने का विधायी उद्देश्य अभियोजन को इस प्रकार के नगण्य तकनीकी कारणों से रुकवाना नहीं है, बल्कि यह बयां करता है कि प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए। हम अपने आप को यह मानने के लिए नहीं समझा पा रहे हैं कि "करेगा" शब्द को एक अनिवार्य प्रावधान के रूप में सख्ती से लिया जाए और समयसीमा के अनुपालन में विफलता से पूरी प्रक्रिया रद्द हो जाती है। इसलिए, हम केरल उच्च न्यायालय द्वारा रूपेश (उपर्युक्त) मामले में लिया गया दृष्टिकोण अस्वीकार करते हैं।

155. हमारा मत है कि विधायी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह द्वि-आदेश अपनी सच्ची भावना में अनुपालन होना चाहिए। हालांकि एक छोटी सी देरी विधायी उद्देश्य को विफल नहीं कर सकती, लेकिन यदि रिकॉर्ड से यह देरी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और वह अस्पष्ट होती है, तो निश्चित रूप से इसका नकारात्मक प्रभाव प्रक्रिया पर पड़ेगा।”

उपरोक्त उद्धरण का अर्थ यह है कि 2008 नियमों के नियम 3 और 4 में उल्लिखित समयसीमा, यद्यपि उनमें 'करेगा' शब्द है, उन्हें केवल मार्गदर्शकके रूप में लिया जाएगा। यदि समयसीमा को कड़ी तरह से लागू किया जाए, तो यह कानून के उद्देश्य को बाधित कर सकता है, जिसका उद्देश्य विशिष्ट प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकना है।

हम यह नोट करते हैं कि उपरोक्त निर्णय से संबंधित एक अपील इस न्यायालय में लंबित है। वर्तमान निर्णय के दौरान, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं और स्पष्ट करते हैं कि उपरोक्त उद्धरण केवल 2008 नियमों में उल्लिखित समयसीमा के संबंध में यह कानूनी प्रश्न निर्धारित करने के लिए है, कि क्या वे अनिवार्य हैं या मार्गदर्शक हैं।

28.5.2 हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय ने, **बिनोद कुमार गंझू उर्फ बिनोद कुमार गंझू उर्फ बिनोद गंझू बनाम भारत संघ32** में इसी तरह के विचार व्यक्त किए और यह निर्णय लिया कि 2008 नियमों में उल्लिखित समयसीमा मार्गदर्शक हैं। इस पर टिप्पणी की गई:

"23. 'रुपेश' में दिया गया निर्णय बाध्यकारी पूर्ववर्ती नहीं है और हम न्यायिक शिष्टाचार और शिष्टता के विचारों से अपने आप को बाध्य नहीं पाते। हम केरल उच्च न्यायालय के 'रुपेश' में किए गए उन टिप्पणियों से सहमत नहीं हैं कि नियम 3 और 4 के तहत प्रदान की गई समयसीमा अनिवार्य है। यह सच है कि यह कोई बहस का मुद्दा नहीं है कि 'shall' शब्द हमेशा कानूनी रूप से अनिवार्य अनुपालन को व्यक्त नहीं करता है। हमारे अनुसार, अनुमति नियम एक समयसीमा निर्धारित करते हैं जो एक मार्गदर्शिका के रूप में होती है, इस पर ध्यान रखते हुए कि एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन न हो, लेकिन इस समयसीमा को अनिवार्य नहीं माना जा सकता और विशेष रूप से उन मामलों में नहीं जहाँ यूएपीए अधिनियम के तहत गंभीर अपराधों के आरोप लगाए गए हैं और एनआईए द्वारा इन्हें प्रारंभिक रूप से सत्यापित किया गया है।"

24. बहुत पहले, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि आपराधिक न्याय प्रणाली को संचालित करने वाला एकमात्र सिद्धांत न्याय का हनन है। यह नियम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के नियमों से उत्पन्न होता है और इसी कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार निष्पक्ष परीक्षण पर जोर दिया है। परीक्षण समाप्त होने पर भी, एक सक्षम अदालत द्वारा दिया गया निर्णय अवैध नहीं माना गया था, जहाँ अदालत ने आरोप तय नहीं किया था [उदाहरण के लिए, बेगू बनाम किंग-एम्पेरर आइएलआर (1925) 6 लह 226]। इस संदर्भ में, हम आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धाराओं 468 से 473 का भी उल्लेख कर सकते हैं, जो संज्ञान लेने के लिए सीमित समय अवधि और कुछ मामलों में अवधि के विस्तार और अपवादों के बारे में बताती हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की योजना इस प्रकार दर्शाती है कि यह हर गड़बड़ी नहीं है जो परीक्षण को शून्य कर देती है, और बहुत अपवादों को छोड़कर अदालत निर्णय को अवैध नहीं मानती। एक आरोपी का मौलिक अधिकार निष्पक्ष परीक्षण का है, जिसमें उसे अपने बचाव के लिए अभियोजन के गवाहों का पूछताछ करने का पर्याप्त अवसर मिलता है, ताकि अभियोजन मामले में झूठेपन को उजागर किया जा सके। लेकिन इसके आगे, एक आरोपी के पास केवल यह वैधानिक अधिकार होता है कि वह यह प्रमाणित कर सके कि जो प्रक्रिया कानून के तहत निर्धारित की गई थी, उसका पालन नहीं किया गया और ऐसी प्रक्रिया की अवहेलना ने उसे अपने बचाव का निष्पक्ष अवसर नहीं दिया, जिसके कारण न्याय का विकृत होना हुआ। जैसा कि ऊपर देखा गया है, अदालत ने यूएपीए अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान लिया है और ऐसे अपराध के लिए आरोप तय किया गया है। हमारी विचारधारा में, इस प्रकार के मामलों में संक्षिप्त नियमों का कोई आवेदन नहीं होगा क्योंकि एक आपराधिक अभियोग को केवल तकनीकी कारणों से विफल नहीं किया जा सकता।

---

32 रिट याचिका (याचिका) 308/2022

28.5.3 एक विपरीत दृष्टिकोण लेते हुए, केरल उच्च न्यायालय ने **रूपेश बनाम केरला राज्य33** मामले में यह निर्णय दिया कि समयसीमा जो निर्धारित की गई है, उसे निर्देशात्मक नहीं माना जा सकता, क्योंकि विधायिका ने इसे स्पष्ट रूप से शामिल किया है। यह निर्णय अन्य समान कानूनों जैसे टाडा या आतंकवाद निरोधक अधिनियम34, 2002 से भिन्न है, जिसमें समयसीमा की अवहेलना को गंभीर माना गया था। केरल उच्च न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

"12. 2008 के नियमों में प्रयुक्त 'करेगा' शब्द का एक स्पष्ट अर्थ है, जैसा कि यूएपीए के धारा 45(1) और (2) में प्रयुक्त समान 'करेगा' शब्द से प्राप्त किया जा सकता है; और केंद्रीय सरकार को कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है, जैसा कि धारा 52 में उल्लेखित है। 2008 के नियमों में सात दिनों का समय निर्धारित किया गया है; जैसा कि अधिनियम में कहा गया है। यह अधिनियम स्वयं व्यक्तियों और संघों की अवैध गतिविधियों को रोकने और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए लागू किया गया है, जिनकी परिभाषाएँ अधिनियम में स्पष्ट रूप से दी गई हैं। इसका संदर्भ उस संदर्भ से लिया जा सकता है जिसमें यह अधिनियम संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने की चुनौती से बचा है, केवल एक उचित अनुमति के आधार पर; जिसे बहुत सख्ती से व्याख्यायित किया जाना चाहिए। संसद ने अधिनियम को पारित करते समय और सरकार ने नियमों को घोषणा करते समय टाडा और पोटा के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 196 का पूर्व अनुभव लिया था; इनमें से कोई भी संप्रभुता और भारत की अखंडता की रक्षा करने के संदर्भ में बिना किसी समय सीमा के आरोप पत्र की स्वीकृति के लिए नहीं था। यूएपीए को मूल रूप से पारित करते समय, इसके उद्देश्य और कारणों की घोषणा में यह कहा गया था कि यह (i) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, (ii) शांति से और बिना शस्त्रों के सभा करने का अधिकार, और (iii) संघों या यूनियनों का गठन करने के अधिकार पर उचित अनुमति लगाने के उद्देश्य से था। मूल अधिनियम में धारा 17 के तहत अभियोजन शुरू करने के लिए केंद्रीय सरकार या अधिकृत अधिकारी से स्वीकृति की आवश्यकता थी।"

14. संसद ने 2008 में, 2008 के संशोधन अधिनियम 35 के तहत, जानबूझकर एक प्रावधान को शामिल किया, जो एक प्राधिकृत प्राधिकरण से अनुशंसा प्राप्त करने की आवश्यकता निर्धारित करता है और उपधारा)1) के अनुसार उपयुक्त सरकार से स्वीकृति की आवश्यकता को बनाए रखा। उपधारा)2) के तहत एक प्राधिकृत प्राधिकरण का प्रावधान था, जो एकत्र किए गए साक्ष्य

---

33 2022 एससीसी ऑनलाइन कर 1372

34 संक्षिप्त में 'पोटा'

35 [2022] 19 एससीआर 563 : सीआरए-डी-5/2023

की समीक्षा करने के बाद अनुशंसा करेगा और इसके लिए नियमों द्वारा एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की जाएगी। केंद्रीय सरकार ने 2008 के नियमों को जारी किया, जिसमें अनुशंसा और स्वीकृति के लिए निर्धारित समय सीमा दी गई थी, यह समय सीमा पवित्र है और हमारे अनुसार, अनिवार्य है। यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि समय की यह निर्धारित सीमा निर्देशात्मक है, और न ही इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 460 (ई या धारा (465 के तहत एक साधारण त्रुटि के रूप में छोड़ा जा सकता है। धारा 460 में कोई भी त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया, जिसमें संज्ञान लेना भी शामिल है, को अच्छे विश्वास में किया गया हो, तो उसे बचाया जा सकता है। जब संज्ञान लेने के लिए स्वीकृति कानूनी रूप से अनिवार्य है और यदि संज्ञान बिना स्वीकृति के या अवैध स्वीकृति के आधार पर लिया जाता है, तो इसे अच्छे विश्वास में लिया गया त्रुटिपूर्ण कार्य नहीं कहा जा सकता और संज्ञान लेने की प्रक्रिया खुद ही रद्द कर दी जाएगी। केरल राज्य, जो इस निष्कर्ष से आहत था कि स्वीकृति कानूनी रूप से गलत थी, ने इस अदालत में अपील दायर की। विशेष अनुमति याचिका संख्या एसएलपी (आपराधिक) संख्या 6981-6983 of 2022 को वापस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया, और कानून के प्रश्न को खुला छोड़ा गया। 28.5.4 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मनजीत सिंह बनाम राज्य पंजाब मामले में समान दृष्टिकोण अपनाया। हालांकि यह मामला ज़मानत के संदर्भ में निर्णय लिया गया था, उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि 2008 नियमों के तहत समयसीमा के अनुसार कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तो आरोपी को अंतरिम ज़मानत का हक होगा। यह निर्णय केरल उच्च न्यायालय द्वारा रूपेश मामले में व्यक्त की गई दृष्टि से सहमत था।

29. इस न्यायालय ने समय सीमा के-भीतर स्वीकृति के मुद्दे पर विचार किया है। पीसी अधिनियम के तहत स्वीकृतियों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय के लिए बोलते हुए न्यायमूर्ति पामिदीघंटम श्री नरसिंह ने ***विजय राजमोहन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो(भ्रष्टाचार निरोधक शाखा)36*** मामले में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए:

"23. अनुमति की स्वीकृति एक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग होने के कारण, यह न्यायिक समीक्षा के मानक सिद्धांतों के अधीन है, जैसे कि स्वतंत्र रूप से विचार करना; केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा, बिना पक्षपाती हुए, प्रासंगिक सामग्री पर विचार करके और अप्रासंगिक विचारों को त्यागते हुए। चूंकि अभियोजन के लिए स्वीकृति देने का अधिकार कानूनी परिणामों को जन्म देता है, इसे स्वाभाविक रूप से एक उचित समयावधि के भीतर प्रयोग में लाना चाहिए। यह सिद्धांत वैसे भी हमारे कानूनी ढांचे में अंतर्निहित है, और हमारे संविधानिक न्यायालयों में विलंब से शक्ति के प्रयोग की वैधता और उचितता की समीक्षा अक्सर की जाती है...

---

36 (2023) 1 एससीसी 329

29. स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी यह ध्यान में रखे कि सार्वजनिक विश्वास, जो कानून के शासन की रक्षा के लिए मौलिक है, यहां दांव पर है। स्वीकृति के अनुरोध पर विचार में विलंब कर, स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी न्यायिक जांच को निष्क्रिय कर देता है, जिससे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आरोपों की निर्धारण प्रक्रिया को दोषपूर्ण कर देता है [*सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह*, (2012) 3 एससीसी 64 : (2012) 1 एससीसी (आपराधिक) 1041 : (2012) 2 एससीसी (एलएंडएस) 666]। भ्रष्टाचार के अभियोजन में विलंब से अभूतपूर्व तरीके से भ्रष्टाचार की संस्कृति फैलती है और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के अस्तित्व के प्रति प्रणालीगत आत्मसमर्पण को बढ़ावा मिलता है। ऐसी निष्क्रियता भविष्य पीढ़ियों को भ्रष्टाचार को जीवन का हिस्सा मानने का खतरा पैदा करती है।..."

32. सबसे पहले, यदि कोई अनिवार्य समयावधि का पालन नहीं किया जाता है, तो इसे स्वचालित रूप से आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का कारण नहीं और नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सार्वजनिक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार के लिए अभियोजन में एक सार्वजनिक हित का तत्व होता है जो कानून के शासन पर सीधे प्रभाव डालता है [*सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह*, (2012) 3 एससीसी 64 : (2012) 1 एससीसी (आपराधिक) 1041 : (2012) 2 एससीसी (एलएंडएस) 666। न्यायमूर्ति ए.के. गांगुली द्वारा : (एससीसी पृष्ठ 102, पैराग्राफ 76-77)"76. स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो दांव पर है वह कानून के शासन में सार्वजनिक विश्वास है, जो न्यायपालिका के प्रशासन में मौलिक है। ऐसी स्वीकृति में विलंब ने कई वैध अभियोजनों को खराब कर दिया है और यह सार्वजनिक दृष्टिकोण में नकारात्मक रूप से देखा जाता है कि स्वीकृति के अनुरोध पर विचार करने के नाम पर भ्रष्ट सार्वजनिक अधिकारी को संरक्षण दिया जा रहा है, जो पहले किए गए या भविष्य में किए गए सेवा के बदले एक प्रतिफल के रूप में हो सकता है, और स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी और भ्रष्ट अधिकारी समान अपराधों में साझेदार रहे हैं या हैं। ... 77. स्वीकृति के अनुरोध पर विचार में विलंब करके, स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी न्यायिक जांच और भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आरोपों की निर्धारण प्रक्रिया को निष्क्रिय कर देता है और इस प्रकार न्यायिक संस्थाओं की वैधता को क्षीण कर देता है। इस प्रकार यह एक नागरिक को उसके वैध और मौलिक अधिकार से वंचित कर देता है, जो अपराधी कानून को गति में लाने के लिए न्याय प्राप्त करने का है और इस प्रकार उसका न्यायिक उपाय तक पहुंचने का अधिकार समाप्त कर देता है, जो एक संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है।"]। यह भी एक तर्कहीन बात है। यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि यदि आपराधिक कार्यवाही स्वचालित रूप से रद्द कर दी जाती है, तो शिकायतकर्ता या पीड़ित के पास न्यायिक समाधान के लिए कोई अन्य उपाय उपलब्ध नहीं है। साथ ही, एक अनुमत स्वीकृति देने का निर्णय अभियुक्त के अधिकारों को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ऐसे मामलों में भी विचारों का अनुप्रयोग नहीं

किया जाएगा।

(उपयुक्त रूप से बल दिया गया)

30. **विजय राजमोहन** (सुप्र) में स्वीकृति के अधिकार को न्यायिक समीक्षा के मानक सिद्धांतों के अधीन होने, हमारे कानूनी ढांचे में इसका अंतर्निहित होना, और यदि कानून का पालन नहीं किया जाता है तो सार्वजनिक विश्वास दांव पर होने जैसी टिप्पणियाँ, हमारे विचार में, यूएपीए के तहत स्वीकृतियों पर भी समान रूप से लागू होंगी। जहाँ तक पीसी अधिनियम का सवाल है, यह कहा गया है कि अनिवार्य समय सीमा का पालन न करना स्वचालित रूप से आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का कारण नहीं बन सकता। यहाँ पर पीसी अधिनियम और यूएपीए के बीच अंतर उभरता है। दोनों अधिनियमों के सामाजिक और कानूनी निहितार्थ भिन्न हैं, क्योंकि यूएपीए में कहीं अधिक गंभीर परिणाम हो सकते हैं। [देखें: तमिलनाडु राज्य बनाम एस. एन. शिवरासन;37 रामभाई नाथाभाई गढ़वी (सुप्र); और अशरफखान (सुप्र)] यूएपीए में स्वीकृति देने की एक विस्तृत प्रक्रिया दी गई है जिसे पालन किया जाना चाहिए और निस्संदेह इसे पूरी तरह से अक्षर और भावना में पालन किया जाना चाहिए।

<u>2008 नियमों का निर्माण</u>

31. यह अच्छी तरह से समझा जाता है कि दंडात्मक विधान ऐसे विधान होते हैं जिनका कड़ाई से व्याख्यान किया जाना चाहिए। यह निर्माण का सिद्धांत बारबार दोहराया गया है। इस संदर्भ - में कुछ प्राधिकरणों का उल्लेख करना यहाँ उपयुक्त है।

31.1 मैक्सवेल ने The इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटुटस (11वीं संस्करण) में यह अवलोकन किया है:

"कड़े निर्माण के नियम का प्रभाव लगभग इस टिप्पणी में संक्षेपित किया जा सकता है कि, जहाँ कोई अस्पष्ट शब्द या अम्बिग्यूस वाक्य उसके अर्थ के बारे में उचित संदेह उत्पन्न करता है, जिसे व्याख्या के नियम हल नहीं कर पाते, वहां संदेह का लाभ विषय को दिया जाना चाहिए और विधानमंडल के खिलाफ, जिसने अपनी बात स्पष्ट नहीं की है। लेकिन यह सर्वोपरि नियम के आगे झुकता है कि प्रत्येक क़ानून को इसके व्यक्त या स्पष्ट उद्देश्य के अनुसार व्याख्यायित किया जाना चाहिए और सभी मामले जो उसके उद्देश्य में आते हैं, यदि भाषा अनुमति देती है, तो उन्हें इसके सुधारात्मक प्रभाव के तहत माना जाना चाहिए।"

---

37. [1996] सप. 8 एससीआर 243: (1997) 1 एससीसी 682

12वीं संस्करण में, इस संदर्भ में किए गए टिप्पणियाँ भी शिक्षाप्रद हैं:

"दंडात्मक क़ानूनों का कड़ा निर्माण चार तरीकों से प्रकट होता है: अपराध के निर्माण के लिए स्पष्ट भाषा की आवश्यकता; अपराध के तत्वों को निर्धारित करने वाले शब्दों की सख्त व्याख्या; दंड देने से पहले कानूनी शर्तों की अक्षरशः पूर्ति की आवश्यकता; और आपराधिक प्रक्रिया और न्यायिक क्षेत्राधिकार से संबंधित तकनीकी प्रावधानों के कड़े पालन की अनिवार्यता।"

31.2 ***स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट मामले में,38*** एक संविधान पीठ ने दंडात्मक क़ानूनों की व्याख्या करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया:

"36. दंडात्मक क़ानूनों की सख्त व्याख्या की आवश्यकता वाला नियम किसी प्रावधान की संकुचित और पेडेंटिक व्याख्या को आवश्यक नहीं मानता, ताकि अपराधी को बचने के लिए कोई छेद छोड़ दिया जाए (देखें ***मुरलीधर मेघराज लोया बनाम महाराष्ट्र राज्य*** [(1976) 3 एससीसी 684 : 1976 एससीसी (क्री) 493])। एक दंडात्मक क़ानून को इस तरह से व्याख्यायित किया जाना चाहिए ताकि कोई अंतराल न रहे, कुप्रभाव को दबाया जा सके और इलाज को बढ़ावा दिया जा सके, जैसा कि हेडन के मामले में निर्धारित किया गया है [(1584) 3 को आरइपी 7ए : 76 इआर 637]। एक सामान्य समझदारी से दंडात्मक क़ानून की लागू होने की स्थिति का समाधान करना, सख्त व्याख्या के नियम द्वारा निषेधित नहीं है। (देखें ***राज्य बनाम बाथु प्रकाश राव*** [(1976) 3 एससीसी 301 : 1976 एससीसी (क्री) 395] और जी. पी. सिंह द्वारा "प्रिंसिपल्स ऑफ़ स्टेट्युटरी इंटरप्रिटेशन", 9वां संस्करण, 2004, अध्याय 11, सारांश 3 पृष्ठ 754 से 756 तक।)"

31.3 ***झारखंड राज्य बनाम अम्बे सीमेंट्स,39*** मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 1995 से संबंधित मुद्दे पर विचार करते हुए दंडात्मक कानूनों की व्याख्या की। न्यायालय ने यह अवलोकन किया:

"26. जब भी कोई विधि यह निर्धारित करती है कि किसी विशेष कार्य को एक विशिष्ट तरीके से किया जाना चाहिए और यह भी निर्दिष्ट करती है कि उस निर्देश का पालन न करने पर गंभीर परिणाम होंगे, तो ऐसे निर्देश को अनिवार्य माना जाएगा। व्याख्या का यह मूलभूत नियम है कि जहां विधि यह प्रदान करती है कि कोई कार्य विशेष तरीके से किया जाना चाहिए, तो उसे उसी

---

38 [2005] सप. 1 एससीआर 49 : (2005) 4 एससीसी 530

39 [2004] सप. 6 एससीआर 125 : (2005) 1 एससीसी 368

निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं। यह भी व्याख्या का स्थापित नियम है कि जहां कोई विधि दंडात्मक प्रकृति की होती है, उसे कड़ाई से समझा और पालन किया जाना चाहिए। चूंकि इस मामले में पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता अनिवार्य है, इसलिए इसका पालन न करने पर अनुदानकर्ता के पक्ष में किए गए रियायत को रद्द करना आवश्यक होगा, जो कि उत्तरदाता है।"

31.4 इस न्यायालय ने ***मंजीत सिंह बनाम सीबीआई40*** मामले में इस पर प्रकाश डाला कि विधियों में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। इसमें यह अवलोकन किया गया, और अन्य प्राधिकरणों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि जब किसी प्रावधान की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध हो, तो न्यायालयों के लिए यह उचित नहीं होगा कि वे किसी काल्पनिक दृष्टिकोण को अपनाएं, जिससे किसी भिन्न निष्कर्ष पर पहुँचा जाए, यह सोचकर कि वह भिन्न निष्कर्ष विधि के उद्देश्य के साथ अधिक संगत होगा।

31.5 ***प्रिया इन्दोरिया बनाम कर्नाटक राज्य41*** मामले में विधि की स्थिति को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया:

"84. मैक्सवेल ने अपनी पुस्तक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटुटस (10वां संस्करण), पृष्ठ 284 में उल्लेख किया है कि 'आधुनिक निर्णयों की प्रवृत्ति समग्र रूप से कठोर और लाभकारी व्याख्या के बीच के अंतर को काफी हद तक कम करने की है।' इसका परिणाम यह है कि दंड विधियां, जैसे कि सीआरपीसी, विधायिका के उद्देश्य और इरादे के साथ तार्किक दृष्टिकोण से व्याख्या की जाती हैं। न्यायिक दृष्टिकोण में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी विधियों की व्याख्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में होनी चाहिए, जब तक कि यह न्याय के निष्पक्ष और प्रभावी प्रशासन के अधीन हो।"

(जोर दिया गया)

32. वैधानिक शक्ति से प्रवाहित नियमों का प्रभाव कानून के समान होता है। यूएपीए की धारा 52 केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। विशेष रूप से, धारा 52 (2)(इइ) वर्तमान स्थिति से संबंधित है, अर्थात यह सरकार को धारा 45 के तहत अनुशंसा और स्वीकृति देने की समयसीमा निर्धारित करने में सक्षम बनाती है।

---

40 [2011] 1 एससीआर 997 : (2011) 11 एससीसी 578

41 [2023] 15 एससीआर 525 : (2024) 4 एससीसी 749

2008 के नियम स्पष्ट रूप से इन दोनों प्रक्रियाओं में, 'shall' शब्द का उपयोग करते हुए, अनुशंसा करने और स्वीकृति देने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा प्रदान करते हैं। उपर्युक्त उच्च न्यायालयों के दृष्टिकोण में, दो ने इसे निर्देशात्मक माना है, जबकि अन्य दो ने इसे अनिवार्य माना है। पहले दृष्टिकोण में, 'shall' शब्द को 'may' के रूप में व्याख्या किया गया है।इस संदर्भ में, कुछ न्यायिक घोषणाओं का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। इस प्रश्न पर जाने से पहले, हम आपराधिक विधियों के संबंध में अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों का भी संदर्भ दे सकते हैं।

32.1 **मॉन्ट्रियल स्ट्रीट रेलवे कंपनी बनाम नॉर्मांडिन42** के मामले में, न्यायिक समिति ने यह विचार किया कि क्या किसी सार्वजनिक निकाय या प्राधिकरण पर कर्तव्य थोपने वाले विधिक प्रावधान अनिवार्य हैं या केवल निर्देशात्मक।

न्यायालय ने यह अवलोकन किया:
"...यह प्रश्न कि किसी विधि में दिए गए प्रावधान अनिवार्य हैं या निर्देशात्मक, इस देश में बार-बार उठ चुका है, लेकिन यह कहा गया है कि कोई सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता और प्रत्येक मामले में विधि के उद्देश्य को देखा जाना चाहिए। इस विषय पर मामलों का संग्रह मैक्सवेल ऑन स्टैच्यूट्स, 5वें संस्करण, पृष्ठ 596 और उसके आगे के पृष्ठों पर मिलेगा। जब विधि के प्रावधान किसी सार्वजनिक कर्तव्य के प्रदर्शन से संबंधित हों और मामला ऐसा हो कि इस कर्तव्य की उपेक्षा में किए गए कार्यों को शून्य और अवैध ठहराने से व्यापक असुविधा या उन व्यक्तियों के प्रति अन्याय हो जो उस कर्तव्य को निभाने वालों पर नियंत्रण नहीं रखते, और यह विधायिका के मुख्य उद्देश्य को भी बढ़ावा नहीं देगा, तो ऐसे प्रावधानों को केवल निर्देशात्मक मानने का प्रचलन रहा है। इस प्रकार की उपेक्षा दंडनीय तो हो सकती है, लेकिन किए गए कार्यों की वैधता को प्रभावित नहीं करती।"

32.2 पांच न्यायाधीशों की पीठ ने ***उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनबोधन लाल श्रीवास्तव43*** मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 की व्याख्या करते हुए, 'shall' और 'may' शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की:
"11. ...इस प्रकार, विधि में 'shall' शब्द का उपयोग आमतौर पर अनिवार्य अर्थ में लिया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक मामले में इसका यही प्रभाव होगा। अर्थात, यदि

---

42 एलआर (1917) एसी 170

43 [1958] 1 एससीआर 533 : 1957 एससीसी ऑनलाइन एससी 4

विधि के शब्दों का सटीकता से पालन नहीं किया जाता है, तो प्रक्रिया या उसके परिणाम स्वतः अमान्य हो जाएंगे। दूसरी ओर, यह कहना भी सही नहीं होगा कि जहां 'may' शब्द का उपयोग किया गया है, वह केवल अनुमति देने वाला या निर्देशात्मक है, इस अर्थ में कि इन प्रावधानों का अनुपालन न करने से प्रक्रिया अमान्य नहीं होगी। इस संदर्भ में, क्रॉफर्ड ऑन स्टैच्यूटरी कंस्ट्रक्शन के अनुच्छेद 261, पृष्ठ 516 से यह उद्धरण प्रासंगिक है:
"यह प्रश्न कि क्या कोई विधि अनिवार्य है या निर्देशात्मक, विधायिका की मंशा पर निर्भर करता है, न कि उस भाषा पर जिसमें मंशा व्यक्त की गई है। विधायिका का उद्देश्य और मंशा ही निर्णायक होनी चाहिए, और इन्हें न केवल प्रावधान की भाषा से, बल्कि उसके स्वरूप, उसकी योजना, और उसके पालन से उत्पन्न होने वाले परिणामों पर विचार करके समझा जाना चाहिए।"

32.3 ***उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बाबू राम उपाध्याय44*** मामले में, एक संविधान पीठ ने 'shall' शब्द की व्याख्या अनिवार्य रूप में करते हुए निम्नलिखित अवलोकन किया:

"29. व्याख्या के प्रासंगिक नियमों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: जब किसी विधि में 'shall' शब्द का उपयोग किया जाता है, तो प्रथम दृष्टया यह अनिवार्य होता है। लेकिन न्यायालय विधि की संपूर्ण परिधि पर ध्यान देकर विधायिका की वास्तविक मंशा का पता लगा सकता है। विधायिका की वास्तविक मंशा जानने के लिए, न्यायालय निम्नलिखित बातों पर विचार कर सकता है: विधि का स्वरूप और डिजाइन, किसी विशेष व्याख्या से उत्पन्न होने वाले परिणाम, अन्य प्रावधानों का प्रभाव, जिनके द्वारा संबंधित प्रावधानों के अनुपालन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, वह स्थिति, जिसमें विधि अनुपालन न होने की संभावना का प्रावधान करती है, यह तथ्य कि प्रावधानों का अनुपालन न करने पर कोई दंड है या नहीं, अनुपालन न करने से उत्पन्न गंभीर या सामान्य परिणाम, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या विधेयक का उद्देश्य विफल होगा या उसे बढ़ावा मिलेगा।"

32.4 ***बच्चन देवी बनाम नगर निगम, गोरखपुर45*** मामले में, इस न्यायालय ने इस व्याख्या नियम पर विस्तार से विचार किया। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"21. सहायक क्रियाओं जैसे 'may' और 'shall' की व्याख्या में अंतिम नियम विधायी मंशा की खोज करना है; और 'may' और 'shall' शब्दों का उपयोग विवेक या अनिवार्यता का निर्णायक प्रमाण नहीं है। इन शब्दों का उपयोग न्यायालयों को विधायी मंशा का पता लगाने में मदद कर सकता है, लेकिन इन्हें नियंत्रणकारी या निर्णायक प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायालयों को विषय-वस्तु, प्रावधानों का उद्देश्य, और विधि द्वारा सुरक्षित किए जाने वाले उद्देश्य, जो सर्वोपरि

---

44 [1961] 2 एससीआर 679 : 1960 एससीसी ऑनलाइन एससी 5

महत्व का है, के साथ-साथ उपयोग किए गए वास्तविक शब्दों पर भी विचार करना चाहिए।"

हालांकि यह मामला भूमि विवाद से संबंधित था, लेकिन 'may' और 'shall' शब्दों के उपयोग पर की गई टिप्पणी वैधानिक व्याख्या के सामान्य सिद्धांत हैं और इसलिए वर्तमान चर्चा के लिए प्रासंगिक हैं।

32.5 ***विजय धनुका बनाम नजीमा ममताज़46*** मामले में, इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में 'may' और 'shall' शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की:

"12. ...'shall' शब्द का उपयोग प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच या विवेचना को अनिवार्य बनाता है। 'shall' शब्द आमतौर पर अनिवार्य होता है, लेकिन कभी-कभी, संदर्भ या मंशा को ध्यान में रखते हुए, इसे निर्देशात्मक भी माना जा सकता है। 'shall' शब्द का उपयोग हर परिस्थिति में निर्णायक नहीं होता। उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, जब हम विधायिका की मंशा पर विचार करते हैं, तो पाते हैं कि इसका उद्देश्य निर्दोष व्यक्तियों को धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा झूठी शिकायतों से उत्पीड़न से बचाना है। इसलिए, हमारे विचार में, 'shall' शब्द का उपयोग, और वह पृष्ठभूमि और उद्देश्य जिसके लिए संशोधन लाया गया है, यह स्पष्ट करता है कि मजिस्ट्रेट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले आरोपी के खिलाफ समन जारी करने से पहले जांच या विवेचना अनिवार्य है।"

32.6 क्रॉफर्ड की "स्टैच्यूटरी कंस्ट्रक्शन" (1989 पुनर्मुद्रण)47 में 'अनिवार्य' और 'निर्देशात्मक' शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

"सामान्यत: 'shall' और 'must' शब्द अनिवार्य होते हैं, जबकि 'may' शब्द निर्देशात्मक होता है, हालांकि इन्हें विधायिका में अक्सर परस्पर स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों का बिना उनके शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दिए उपयोग आमतौर पर न्यायालयों को व्याख्या करने की आवश्यकता बना देता है ताकि विधायिका की वास्तविक मंशा का पता लगाया जा सके। फिर

---

45 [2008] 2 एससीआर 424 : (2008) 12 एससीसी 372

46 [2014] 4 एससीआर 171 : (2014) 14 एससीसी 638

47 भारतीय संघ बनाम ए.के पांडेय, (2009) 10 एससीसी 552 में उद्धृत

भी, न्यायालय यह मानकर चलता है कि विधायिका ने शब्दों का उनके सामान्य और प्राकृतिक अर्थ में उपयोग करने का इरादा किया होगा। यदि ऐसा अर्थ, हालांकि, असंगतता, अत्यधिक असुविधा या किसी अन्य कारण से विधायिका की स्पष्ट मंशा के विपरीत प्रतीत होता है, तो जो शब्द सामान्यतः अनिवार्य होते हैं, उन्हें निर्देशात्मक के रूप में या इसके विपरीत समझा जा सकता है। यदि विधि की भाषा, इसके समग्र संदर्भ में और इसके स्वरूप तथा उद्देश्य के अनुसार, यह दर्शाती है कि विधायिका ने 'shall' और 'must' शब्दों को निर्देशात्मक रूप में उपयोग करने का इरादा किया था, तो इन्हें उसी अर्थ में लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, समान परिस्थितियों में, 'may' शब्द को अनिवार्य अर्थ में समझा जाना चाहिए, विशेष रूप से जब विधि का संबंध सार्वजनिक अधिकारों और हितों से हो, या जब तृतीय पक्षों का वैध अधिकार हो कि कोई शक्ति प्रयोग में लाई जाए, या जब किसी कार्य को न्याय या सार्वजनिक भलाई के लिए किया जाना आवश्यक हो, या विधि की संवैधानिकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो।

हालांकि, अनिवार्य शब्दों को निर्देशात्मक और निर्देशात्मक शब्दों को अनिवार्य रूप में समझने की व्याख्या को हल्के में नहीं अपनाना चाहिए। इसके विपरीत अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह खतरा रहता है कि विधायिका की मंशा पूरी तरह या आंशिक रूप से विफल हो सकती है।"

(जोर दिया गया)

33. कठोर निर्माण के मामलों में, जब कोई समय सीमा निर्धारित की जाती है, साथ ही 'shall' शब्द का उपयोग किया जाता है, और विशेष रूप से जब यह कोई कानून जैसे यूएपीए के संदर्भ में होता है, तो इसे केवल एक तकनीकीता या औपचारिकता नहीं माना जा सकता। यह विधायिका की स्पष्ट मंशा को दर्शाता है। एक बाध्यता लागू की गई है, और उस बाध्यता का पालन करने के लिए एक समय सीमा प्रदान की गई है। जबकि यह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक अवैध गतिविधियों और प्रथाओं को रोकने के उद्देश्य से है और इसके अनुसार सरकार को कानून के तहत अनुमत सभी प्रक्रियाओं और कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान करता है, वहीं आरोपी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा भी जरूरी है। यह उम्मीद की जाती है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के आदर्श को आगे बढ़ाते हुए, त्वरित और सक्रिय रूप से कार्य करेगी। बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई चिंता यह है कि समय सीमा की कठोर व्याख्या कानून के उद्देश्य को विफल कर सकती है। पहली नजर में यह बयान आकर्षक लगता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दी गई समय सीमा केवल सामग्री की स्वतंत्र समीक्षा करने और फिर सिफारिश करने के लिए है, उसके बाद अनुमति देने वाली प्राधिकरण उन

सामग्रियों और सिफारिशों पर विचार कर अंततः अनुमति देने या न देने का निर्णय ले सकती है। यह स्वयं जांच के उद्देश्य के लिए नहीं है, जो समझा जा सकता है कि एक समय-संवेदनशील प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि इसमें कई चर शामिल होते हैं। सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों के पास अपनी शक्तियाँ प्रयोग करने के लिए कुछ सीमाएँ होनी चाहिए। बिना ऐसी सीमाओं के, शक्ति निरंकुश हो सकती है, जो कि, यह कहना अवश्यक है, एक लोकतांत्रिक समाज के लिए प्रतिकूल है। इस प्रकार के मामलों में समय सीमा निगरानी और संतुलन के आवश्यक पहलू के रूप में कार्य करती है और निश्चित रूप से, यह सवाल से परे महत्वपूर्ण है। यदि बॉम्बे और झारखंड उच्च न्यायालयों का दृष्टिकोण कायम रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह न्यायिक शाखा द्वारा विधायिका के दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने के समान होगा, जो कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के तहत अस्वीकार्य है। हमें अपनी दृष्टि के समर्थन में संविधान पीठ के निर्णय ***ए.आर अंतुले बनाम रामदास श्रीनिवास नायक48*** में समर्थन प्राप्त होता है, जहाँ न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

"18. यह एक स्थापित निर्माण सिद्धांत है कि अदालत को धारा को जैसा है, वैसे पढ़ना चाहिए और इसे अपनी सुविधा के अनुसार फिर से नहीं लिख सकती; न ही कोई निर्माण सिद्धांत अदालत को ऐसा पढ़ने की अनुमति देता है जिससे उसे कुछ हद तक निरर्थक बना दिया जाए।"

[देखें: ***यूनियन ऑफ इंडिया बनाम देवकी नंदन अग्रवाल;49 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बनाम प्राइस वाटरहाउस;50* और शिव शक्ति सहकारी हाउसिंग सोसाइटी बनाम स्वराज डेवलपर्स51***]

विधायिका की मंशा स्पष्ट है। वैधानिक शक्तियों के तहत बनाए गए नियम दोनों, एक आदेश और एक समय सीमा, को निर्धारित करते हैं। इसका पालन किया जाना चाहिए। यहाँ पर हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि 2008 के नियम 3 और 4 में उल्लिखित समय सीमा का कड़ाई से पालन करने के संबंध में जो निष्कर्ष हमने निकाला है, वह किसी भी निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा, जहाँ इसे आज के निर्णय की तारीख तक पालन किया गया हो या नहीं। स्पष्टता के लिए, यह कहा जाता है कि इस निर्णय में किए गए विचार केवल भविष्य में लागू होंगे।

स्वतंत्र समीक्षा

34. इस संबंध में विवाद का मुख्य बिंदु यह है कि चूंकि सिफारिश करने वाली और अनुमोदन करने वाली दोनों प्राधिकृत संस्थाओं ने अपने-अपने कार्यों को केवल एक दिन में पूरा किया, इस कारण से दोनों प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला स्वतंत्र समीक्षा का आवश्यकता पूरी नहीं की गई, जिससे संबंधित अनुमोदन प्रभावित हो गया है।

35. शब्द "स्वतंत्र" का अर्थ, जैसा कि सामान्यतः समझा जाता है, यह है कि कार्य, या इस मामले में, मूल्यांकन इस तरीके से किया जाता है जो अकेले खड़ा हो या जो किसी अन्य कारक पर निर्भर न हो, जैसे कि किसी अन्य प्राधिकृत संस्था द्वारा पूर्व में किए गए विचार या मूल्यांकन, जिससे इसका निष्कर्ष निकाला गया हो।

35.1 कैम्ब्रिज डिक्शनरी में – :शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है "स्वतंत्र"
“किसी अन्य व्यक्ति, घटना या वस्तु द्वारा किसी भी प्रकार से प्रभावित या नियंत्रित नहीं होने वाला”

35.2 मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी में "स्वतंत्र" शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: -

“1: निर्भर न होना: जैसे
a (1): दूसरों द्वारा नियंत्रित न होना; (2): एक बड़े नियंत्रित इकाई से संबद्ध न होना
b (1): किसी अन्य पर निर्भर या आधारित न होना: परिस्थितियों पर निर्भर न होना; (2): दूसरों से राय या आचरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता न होना; (3): किसी राजनीतिक पार्टी से बंधे या प्रतिबद्ध न होना
c (1): दूसरों पर निर्भर या आधारित न होना (जैसे देखभाल या आजीविका के लिए); (2): इतना पर्याप्त होना कि किसी को जीविकोपार्जन के लिए काम करने की आवश्यकता न हो
d: स्वतंत्रता की इच्छा दिखाना”

35.3 ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में "स्वतंत्र" शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:
“स्वतंत्र. निर्भर नहीं; किसी दिए गए बाहरी स्रोत से नियंत्रण, अनुमति, संशोधन, या सीमा के अधीन नहीं।”

स्वतंत्रता, जो स्वतंत्र होने की स्थिति है, हमारे समझ में भी मार्गदर्शक होगी।
“स्वतंत्रता. निर्भरता, अधीनता, या नियंत्रण से मुक्त होने की स्थिति या अवस्था। पूर्ण उत्तरदायित्वहीनता की स्थिति। राजनीतिक स्वतंत्रता उस राष्ट्र या राज्य का गुण है जो पूरी तरह से स्वायत्त होता है, और किसी बाहरी शक्ति के सरकार, नियंत्रण, या आदेश के अधीन नहीं होता।”

---

48 [1984] 2 एससीआर 914 : (1984) 2 एससीसी 500
49 [1991] 3 एससीआर 873 : 1992 सप (1) एससीसी 323
50 [1997] Supp. 2 एससीआर 267 : (1997) 6 एससीसी 312
*"सग़ीर अहमद,न्यायाधीश का विपरीत मत
51 [2003] 3 एससीआर 762 : (2003) 6 एससीसी 659

36. समीक्षा, एक अवधारणा के रूप में, को समझा जाना चाहिए क्योंकि इन दोनों पहलुओं का संगम ही 'स्वतंत्र समीक्षा' शब्द की हमारी समझ को रूप देती है।

36.1 कैम्ब्रिज डिक्शनरी में 'समीक्षा' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:
"किसी चीज़ के बारे में फिर से सोचने या बात करने का मतलब, ताकि उसमें बदलाव किया जा सके या उस पर कोई निर्णय लिया जा सके।"

36.2 मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी में 'समीक्षा' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:
"…2: विशेष रूप से न्यायिक रूप से फिर से जांचना या अध्ययन करना...
4a: आलोचनात्मक रूप से या जानबूझकर पुनः विचार या जांच करना;
b: आलोचनात्मक मूल्यांकन देना।"

36.3 बर्टन के लीगल थिसॉरस52 में 'समीक्षा' के समान शब्दों के रूप में निम्नलिखित शब्द सूचीबद्ध हैं – विश्लेषण करना; टिप्पणी करना; ध्यान से विचार करना; आलोचना करना; जांच करना; समीक्षा करना; विचार करना; फिर से परीक्षण करना; सघनता से जांचना; अध्ययन करना और तौलना।

37. 'स्वतंत्र समीक्षा' शब्द का अर्थ, जैसा कि ऊपर से समझा जा सकता है, कुछ की पुनः जाँच, सघनता से मूल्यांकन या आलोचना है, जो किसी अन्य कारक या प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित या निर्भर नहीं है। वर्तमान तथ्यों में, स्वतंत्र समीक्षा का मतलब होगा जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए सामग्री का अध्ययन या विचार, ताकि यह निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि क्या यूएपीए की धाराओं के तहत कार्यवाही करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। इसी प्रकार, अगले चरण में, स्वीकृति देने वाली प्राधिकरण को एकत्र की गई सामग्री और अनुशंसा करने वाली प्राधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्षों पर आलोचनात्मक रूप से विचार करना और गौर करना होगा, ताकि अनुमति प्रदान की जा सके।

38. यूएपीए की धारा 45 में 31 दिसंबर 2008 से प्रभावी किए गए संशोधन के तहत स्वतंत्र समीक्षा के पहलू को लाने का विधायी उद्देश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए।

39. गृह मंत्री ने राज्य परिषद में मसौदा विधेयकों को प्रस्तुत करते हुए इस प्रकार की प्रस्तावना की मंशा को रेखांकित किया, जैसा कि नीचे उद्धृत किया गया है:

---

52 तीसरा संस्करण; पृष्ठ 473

"अंत में, सर, हमने एक बहुत ही उपयोगी प्रावधान शामिल किया है। हमारी जानकारी के

अनुसार-मैं नहीं जानता, मुझे बाद में कानून मंत्री या कानून सचिव द्वारा इसे सही किया जा सकता है- यह पहली बार है जब हम इसे पेश कर रहे हैं। यूएपीए के तहत अभियोजन में, अब यह कार्यकारी सरकार है जो पुलिस अधिकारी के माध्यम से मामला दर्ज करती है। यह कार्यकारी सरकार है जो जांच करती है, अर्थात पुलिस विभाग के माध्यम से। यह कार्यकारी सरकार है जो धारा 45 के तहत स्वीकृति प्रदान करती है। इसलिए, एक प्रतिशोधात्मक या गलत कार्यकारी सरकार द्वारा मामला दर्ज करने, जांच करने और अभियोजन को स्वीकृति देने का भय है। यह भय हो सकता है, शायद यह एकदम सही नहीं है लेकिन आप नहीं कह सकते कि यह पूरी तरह से अन्यथा है। तो हम क्या कर रहे हैं? कार्यकारी सरकार मामला दर्ज कर सकती है क्योंकि कोई

और मामला दर्ज नहीं कर सकता। कार्यकारी सरकार, इसके एजेंसी के माध्यम से, मामले की जांच कर सकती है। लेकिन, धारा 45(1) के तहत स्वीकृति दी जाने से पहले हम एक स्वतंत्र

प्राधिकरण को प्रवेश करवा रहे हैं जो पूरी जांच सामग्री की समीक्षा करेगा और फिर यह अनुशंसा करेगा कि क्या यह अभियोजन के लिए एक उपयुक्त मामला है। तो, यहाँ हम एक फ़िल्टर, एक बफ़र, एक स्वतंत्र प्राधिकरण ला रहे हैं जिसे पूरी जांच सामग्री की समीक्षा करनी होगी और फिर राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार को, जैसा भी मामला हो, एक उपयुक्त मामला होने की अनुशंसा करनी होगी। मुझे लगता है, यह एक बहुत ही उपयोगी सुरक्षा उपाय है। सदन के सभी सदस्यों को इसका स्वागत करना चाहिए। यह मनमानी के खिलाफ सबसे बड़ा बफ़र है जिस पर कई सदस्यों ने बात की थी। सर, विधेयक में ये विशेषताएँ हैं।"

उपरोक्त उद्धृत बयान में, यह विचार, उद्देश्य और मंशा स्पष्ट रूप से दी गई है कि स्वतंत्र प्राधिकरण को इसलिये लाया गया था ताकि जांच एजेंसी द्वारा एकत्रित सामग्री की समीक्षा की जा सके, इससे पहले कि सरकार स्वीकृति जारी करे या खारिज करे। यह कार्यकारी सरकार की शक्ति पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से किया गया था।

40. उपर्युक्त से यह निकलता है कि इस प्राधिकरण की स्वतंत्रता अनिवार्य है, इसके बिना इसका पूरा उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अब विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि कैसे यह निर्धारित किया जा सकता है कि कोई विशिष्ट प्रक्रिया स्वतंत्रता के साथ चमकी थी या फिर इसे बाहरी प्रभावों के बादल ने प्रभावित किया था, जो इसके चरित्र को कमजोर कर सकते थे।

40.1 ***सी.एस. कृष्णमूर्ति बनाम कर्नाटका राज्य53*** में, न्यायालय ने पी.सी. एक्ट के तहत संज्ञान आदेश के संदर्भ में कहा था:

"9. इसलिए, इसका तात्पर्य यह है कि संज्ञान आदेश को खुद के लिए बोलना चाहिए और यदि तथ्य इस प्रकार नहीं दिखते हैं, तो यह यह साबित करना चाहिए कि सभी विवरणों को संज्ञान प्राधिकरण के सामने उचित विचार के लिए रखा गया था। यदि संज्ञान आदेश अपने आप में स्पष्ट है, तो संज्ञान प्राधिकरण की संतुष्टि आदेश को पढ़कर स्पष्ट होती है..."

इसका उल्लेख ***मध्य प्रदेश राज्य बनाम हरिशंकर भगवान प्रसाद त्रिपाठी54*** में भी किया गया था।

40.2 ***महाराष्ट्र राज्य बनाम महेश जी. जैन 55*** में, कई अधिकारियों पर विचार करने के बाद, जिनमें से कुछ पहले इस मामले में उद्धृत किए गए थे, निम्नलिखित तत्व निकाले गए:

“14.1. अभियोजन पर यह जिम्मेदारी है कि वह यह प्रमाणित करे कि वैध संज्ञान प्राधिकरण द्वारा संज्ञान प्रदान किया गया है, यह साबित करने के बाद कि संज्ञान के लिए मामला तैयार किया गया है।

14.2. संज्ञान आदेश यह स्पष्ट रूप से दिखा सकता है कि संज्ञान प्राधिकरण ने उसके सामने रखे गए सामग्रियों की समीक्षा की है और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अभियोजन के लिए संज्ञान प्रदान किया है।"

14.3. अभियोजन यह प्रमाणित कर सकता है कि प्रमाण प्रस्तुत करके यह दिखाया जाए कि सामग्री संज्ञान प्राधिकरण के समक्ष रखी गई थी और उसकी संतुष्टि सामग्री की समीक्षा करने के बाद प्राप्त की गई थी।

14.4. संज्ञान प्रदान करना केवल एक प्रशासनिक कार्य है और संज्ञान प्राधिकरण को यह प्रारंभिक रूप से संतुष्ट होना चाहिए कि संबंधित तथ्य अपराध का गठन करेंगे।

14.5. संज्ञान प्राधिकरण के समक्ष रखी गई सामग्री की पर्याप्तता को न्यायालय द्वारा नहीं देखा जा सकता क्योंकि न्यायालय संज्ञान आदेश पर अपील नहीं करता है।

14.6. यदि संज्ञान प्राधिकरण ने उसके समक्ष रखी गई सभी सामग्रियों की समीक्षा की है और उनमें से कुछ को प्रमाणित नहीं किया गया है, तो यह संज्ञान आदेश को निरस्त नहीं करेगा।

14.7. संज्ञान आदेश एक पूर्वशर्त है क्योंकि इसका उद्देश्य एक सार्वजनिक सेवक को निराधार और परेशान करने वाले मुकदमेबाजों से सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन साथ ही संज्ञान आदेश को

रूढ़िवादी तरीके से व्याख्यायित नहीं किया जाना चाहिए और इसकी वैधता की जांच में अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए।

उसी फैसले में यह देखा गया कि "संज्ञान प्रदान करना एक पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य है " जिसका उद्देश्य एक सार्वजनिक सेवक को परेशान करने वाले मुकदमेबाजों से सुरक्षा प्रदान करना है। हालांकि, जब संज्ञान आदेश)a) एक सक्षम प्राधिकरण द्वारा और)b) उचित विचार के बाद दिया जाता है, तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता या, दूसरे शब्दों में, इसे त्वरित रूप से खारिज नहीं किया जा सकता।

40.3 हाल ही में, ***जजबीर सिंह बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी में,56*** 2008 नियमों के नियम 3 और 4 के लागू होने की जांच करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित कहा:

"50. ... हम 'जांच अधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत एकत्रित साक्ष्य की प्राप्ति के 7 कार्यदिवसों के भीतर' इस शब्द पर बल देते हैं। यह साक्ष्य, जिसे 2008 के नियम 3 में परिकल्पित किया गया है, वह अंतिम रिपोर्ट है, यानी, वह रिपोर्ट जिसे जांच एजेंसी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत दायर करती है। कैसे कोई यह उम्मीद कर सकता है कि धारा 45 की उपधारा (2) के तहत प्राधिकरण अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें सिफारिशें हों, बिना जांच अधिकारी द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्य को पूरी तरह से देखे? **इसके विपरीत, 2008 के नियम 3 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यूएपीए की धारा 45 की उपधारा (2) के तहत प्राधिकरण कानूनी रूप से बाध्य है कि वह जांच अधिकारी द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्य पर पूरी तरह से विचार करे और उसके बाद, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को संज्ञान देने के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करे। संज्ञान का प्रदान करना कोई औपचारिकता नहीं है। संज्ञान का प्रदान करना उचित विचार की प्रक्रिया को दर्शाना चाहिए**।"

40.4 ***पंजाब राज्य बनाम मोहम्मद इकबाल भट्टी में,57*** कानून की स्थिति इस प्रकार व्यक्त की गई:

---

53 [2005] 2 एससीआर 1163 : (2005) 4 एससीसी 81

54 [2010] 9 एससीआर 1148 : (2010) 8 एससीसी 655

55 [2013] 3 एससीआर 850 : (2013) 8 एससीसी 119

56 [2023] 6 एससीआर 1: 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 543

57 [2009] 11 एससीआर 790 : (2009) 17 एससीसी 92

"7. संज्ञान आदेश की वैधता संबंधित प्राधिकरण के द्वारा विचार की प्रक्रिया और उसके सामने रखे गए सामग्री पर निर्भर करेगी। सभी ऐसे तथ्य और सामग्री साक्ष्य जिन्हें उसने ध्यान में रखा है, उसे विचार करना चाहिए। संज्ञान प्राधिकरण को जांच के दौरान एकत्रित किए गए ऐसे तथ्य और साक्ष्यों पर विचार करना चाहिए। यदि संज्ञान आदेश से इस प्रकार की विचार प्रक्रिया नहीं दिखती है, तो इस संदर्भ में कोर्ट के सामने बाहरी साक्ष्य पेश किए जा सकते हैं। संज्ञान प्रदान करते समय, प्राधिकरण अप्रासंगिक तथ्य को ध्यान में नहीं रख सकता और न ही वह किसी बाहरी विचार के आधार पर आदेश पारित कर सकता है जो कानूनी आदेश पारित करने के लिए प्रासंगिक न हो। यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि उच्च न्यायालय संज्ञान प्राधिकरण को न तो संज्ञान देने का आदेश दे सकता है और न ही इसे न देने का आदेश दे सकता है..."

40.5 ***राज्य (दिल्ली एनसीटी) बनाम नवजोत संधू***[58] में इस न्यायालय ने '2001 संसद हमले' के संदर्भ में टाडा के प्रावधानों और योजना की विस्तृत रूप से समीक्षा की। वर्तमान फैसले के लिए संज्ञान से संबंधित कुछ अवलोकन प्रासंगिक हैं। उन्हें इस प्रकार संक्षेपित किया गया है:

40.5.1 यह विचार करना है कि क्या आरोपों के आधार के रूप में जो सामग्री थी, वह वास्तव में प्राधिकरण के सामने रखी गई थी।

40.5.2 एफआइआर या ड्राफ्ट चार्जशीट की सामग्री को दोहराना विचार या मन की प्रक्रिया नहीं मानी जाती। यह उससे कुछ आगे का होना चाहिए।

40.5.3 संज्ञान आदेश या सिफारिश या संज्ञान प्रदान करने का आदेश, दोनों को अपने चेहरे पर सभी प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने को दर्शाना चाहिए।

40.5.4 संज्ञान आदेशों का मूल्यांकन करते समय जो मानक अपनाया जाता है, वह वही नहीं है जो न्यायिक निकायों के आदेशों के लिए लागू होता है, क्योंकि यह एक विशुद्ध प्रशासनिक कार्य है।

40.6 बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा[59] में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ शिक्षाप्रद हैं। संबंधित अंश इस प्रकार है:

---

58 [2005] सप. 2 एससीआर 79 : (2005) 11 एससीसी 600

59 1992 सप. (1) एससीसी 222

"27. धारा 197 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत संज्ञान एक खाली औपचारिकता नहीं है। यह आवश्यक है कि इसके प्रावधानों का पालन पूरी सख्ती से किया जाए। संज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य यह है कि संबंधित प्राधिकरण स्वयं जांच अधिकारी के सामने रखी गई सामग्री पर विचार कर सके, इससे पहले कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि परिस्थितियों में अभियोजन को संज्ञान दिया जाए या नकारा जाए। धारा 197 के प्रावधानों का पालन करने के लिए यह साबित करना होगा कि संज्ञान अपराध के तथ्य जो आरोपित किए गए हैं, के संबंध में दिया गया था। यह वांछनीय है कि तथ्यों का उल्लेख संज्ञान आदेश में स्पष्ट रूप से किया जाए। धारा 197 संज्ञान के किसी विशेष रूप में होने की आवश्यकता नहीं रखती। यदि आरोपित अपराध के तथ्य संज्ञान आदेश में नहीं दिखाए गए हैं, तो अभियोजन को यह साबित करने का अवसर है, यदि चुनौती दी जाती है, कि वे तथ्य संज्ञान प्राधिकरण के सामने रखे गए थे। संज्ञान आदेश के रूप से यह स्पष्ट होना चाहिए कि संज्ञान प्राधिकरण ने उसके सामने रखी गई प्रासंगिक सामग्री पर विचार किया और मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अभियोजन को संज्ञान दिया।"

(जोर दिया गया)

41. ऊपर उल्लिखित कानून की स्थिति पर ध्यान देने के बाद, अब हम वर्तमान तथ्यों की ओर रुख करते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो, अपीलकर्ता का आपत्ति उस कम समय से उत्पन्न होती है जो संज्ञान सिफारिश करने और उसे देने में लिया गया, जिसे वह मानसिक विचार की अनुपस्थिति और स्वतंत्र समीक्षा की कमी का संकेत मानते हैं। हम इस प्रकार के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दिखाता हो कि प्रासंगिक सामग्री प्राधिकरणों के समक्ष नहीं रखी गई थी। न ही प्राधिकरणों की क्षमता पर कोई प्रश्न उठाया जा सकता है, जैसा कि सही तरीके से नहीं उठाया जा सकता। इसलिए, केवल इस आधार पर कि लिया गया समय तुलनात्मक रूप से कम था या यहां तक कि अन्य आदेश समान शब्दों में थे, संज्ञान की विश्वसनीयता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। जैसा कि ***पुलिस अधीक्षक (सीबीआइ) बनाम दीपक चौधरी***[60] में उल्लेखित किया गया है, प्राधिकरणों को केवल यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि क्या जांच में एकत्रित किए गए प्रासंगिक तथ्य अपराध का गठन करेंगे या नहीं। ***महेश जी. जैन*** (उपरोक्त) में यह तय किया गया है कि अभियोजन को यह प्रमाणित करना होता है कि वैध संज्ञान प्रदान किया गया है। यह कहना न होगा कि यह

---

60 [1995] सप. 2 एससीआर 818 : (1995) 6 एससीसी 225

केवल मुकदमे में साक्ष्य प्रस्तुत करके किया जा सकता है, जहां रक्षा पक्ष को इसमें चुनौती देने का अवसर दिया जाएगा और यह मामला आगे रखा जाएगा कि ऊपर वर्णित दो आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया गया है। आगे ***मोहमद इकबाल एम. शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य61 में*** जो एक टाडा मामला था, इस न्यायालय को समान स्थिति का सामना करना पड़ा, जहां संज्ञान सक्षम प्राधिकरण, अर्थात्, ग्रेटर बॉम्बे के पुलिस आयुक्त द्वारा उसी दिन दिया गया था, जिस दिन उसने इस संदर्भ में संबंधित कागजात प्राप्त किए थे। मानसिक विचार की अनुपस्थिति का तर्क न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, यह कहते हुए कि जब तक संज्ञान सक्षम प्राधिकरण द्वारा दिया गया था और सभी सामग्रियों पर विचार करने के बाद, और वही आदेश में व्यक्त किया गया, तब तक संज्ञान वैध माना जाएगा। इसके अलावा यह कहा गया कि जब आदेश में ऐसा संकेत नहीं होता, तो अभियोजन को संज्ञान देने वाले व्यक्ति के बारे में बाहरी साक्ष्य पेश करने का अधिकार है और यह पर्याप्त पालन होगा। फिर न्यायालय इस प्रकार के साक्ष्य की समीक्षा करेगा और यह निर्णय लेगा कि मानसिक विचार था या नहीं। निष्कर्ष में, हम यह मानते हैं कि स्वतंत्र समीक्षा और मानसिक विचार दोनों ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें साक्ष्य द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए और इसलिए इन्हें मुकदमे के चरण में उठाया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन कारणों से कार्यवाही में कोई अनावश्यक देरी न हो और वह अपनी कानूनी और तार्किक परिणति तक पहुंच सके। इस न्यायालय द्वारा पहले मुद्दे पर उठाए गए निष्कर्ष के परिणामस्वरूप यह भी कहा जाना चाहिए कि यदि संज्ञान को ऊपर बताए गए कारणों पर अपत्ति की जाती है, तो इसे शीघ्र उठाया जाना चाहिए, न कि देर से, हालांकि कानून इसे बाद में चुनौती देने से रोकता नहीं है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यूएपीए की योजना में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है जैसे कि पीसी अधिनियम62 की धारा 19, जो उन कार्यवाहियों को सुरक्षा प्रदान करती है जो संज्ञानों के आधार पर शुरू की जाती हैं और जिन्हें बाद में चुनौती दी जाती है, इसलिए न्यायालयों को देर से उठाए गए विवादों को स्वीकार करते समय सतर्क रहना चाहिए। यदि यह देर से उठाया जाता है, तो न्यायालय को मामले की मेरिट पर विचार करने से पहले देरी के कारणों पर विचार करना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इन कारणों पर देर से उठाए गए विवादों को मुकदमे में रुकावट के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और न ही इसे उन दोषसिद्धियों से बचने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जो अन्यथा वैध रूप से संचालित अभियोजनों और मुकदमों से उत्पन्न होते हैं।

प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को न्यायिक समीक्षा द्वारा उसी आधार पर परखा नहीं जाता है जैसे कि न्यायिक या अर्ध-न्यायिक आदेश को परखा जाता है। जबकि बाद वाले के लिए एक विशेष निर्णय पर पहुंचने के कारणों को दर्ज करना अनिवार्य होता है, पूर्व के लिए यह पर्याप्त है कि यह दिखाया जाए कि आदेश पारित करने वाले प्राधिकरण ने संबंधित तथ्यों और

सामग्रियों पर विचार किया। [देखें: पी.पी. शर्मा (उपरोक्त); नवजोत संधू (उपरोक्त) और महेश जी. जैन (उपरोक्त)]। यह मान्य स्थिति है, हम ए -17 के खिलाफ संज्ञान देने वाले आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। ऐसा प्राधिकरण पर यह अनिवार्य नहीं है कि वह अपने निष्कर्ष को समर्थन देने के लिए विस्तृत कारण दर्ज करे और इस प्रकार, यहां चुनौती दिए गए आदेश को इस आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

---

61 [1998] 2 एससीआर 734 : (1998) 4 एससीसी 494

62 **19. अभियोजन के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक**...

(3) भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 of 1974) में निहित किसी भी बात के बावजूद,—

(a) किसी विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित कोई निर्णय, सजा या आदेश अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण में इस आधार पर पलटा या बदला नहीं जाएगा कि उप-धारा (1) के अंतर्गत आवश्यक स्वीकृति की अनुपस्थिति, या उसमें कोई त्रुटि, चूक या अनियमितता है, जब तक कि उस न्यायालय के अनुसार, वास्तव में न्याय का हनन हुआ हो;

(b) कोई न्यायालय इस अधिनियम के तहत कार्यवाही को उस आधार पर स्थगित नहीं करेगा कि प्राधिकरण द्वारा दी गई स्वीकृति में कोई त्रुटि, चूक या अनियमितता है, जब तक कि यह संतुष्ट न हो कि ऐसी त्रुटि, चूक या अनियमितता ने न्याय के हनन का कारण बनी है;

(c) कोई न्यायालय इस अधिनियम के तहत कार्यवाही को किसी अन्य आधार पर स्थगित नहीं करेगा और कोई न्यायालय किसी जांच, परीक्षण, अपील या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतरिम आदेश के संबंध में पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा।

(4) उप-धारा (3) के तहत यह निर्धारित करते समय कि ऐसी स्वीकृति की अनुपस्थिति, या उसमें कोई त्रुटि, चूक या अनियमितता ने न्याय के हनन का कारण बना है या नहीं, न्यायालय को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपत्ति को कार्यवाही के किसी पूर्व चरण में उठाया जा सकता था और इसे उठाना चाहिए था।

व्याख्या.—इस धारा के उद्देश्यों के लिए,—

(a) त्रुटि में प्राधिकरण की स्वीकृति देने की क्षमता शामिल है;

(b) अभियोजन के लिए आवश्यक स्वीकृति में किसी विशेष प्राधिकरण के अनुरोध पर अभियोजन होने की आवश्यकता या किसी विशेष व्यक्ति की स्वीकृति के साथ अभियोजन होने की आवश्यकता या इसी प्रकार की किसी आवश्यकता का संदर्भ शामिल है।

मुद्दा संख्या 3 – आरोपों का मिश्रण और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन

42. अपीलकर्ता का तर्क है कि दो अलग-अलग घटनाओं को एक साथ जोड़कर उसे आरोपी और बड़े षड्यंत्र का सदस्य बना दिया गया है। दूसरी ओर, प्रतिवादी-यूनियन का कहना है कि सभी घटनाएँ (पहला मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल, साथ ही वह घटना जिसके लिए अपीलकर्ता को आरोपी बनाया गया था) आपस में जुड़ी हुई हैं और पहली संज्ञान से उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ताओं का आरोप है कि एनआइए द्वारा शक्तियों का गंभीर दुरुपयोग किया गया है और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 218-224 का उल्लंघन हुआ है।

43. धारा 218 दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XVII में आती है, जिसका शीर्षक है 'आरोप' और विशेष रूप से इसके भाग बी में, जो आरोपों के मिश्रण से संबंधित है। एक अर्थ में, अपीलकर्ता ने अध्याय के पूरे भाग का उल्लंघन होने का आरोप लगाया है, जो कि पहली नज़र में स्वीकार करना कठिन है। यह पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब कोई व्यक्ति किसी धारा या क़ानून के भाग के उल्लंघन का आरोप लगाता है, तो उसे यह प्रमाणित करना होता है कि उस धारा के किस पहलू का पालन नहीं किया गया और उस अनुपालन की कमी ने उसे किस प्रकार से नुकसान पहुँचाया है। इस मामले में, हालांकि, हम दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन का एक व्यापक बयान देख रहे हैं, जिसमें यह समझाने के लिए बहुत कम या बिल्कुल भी स्पष्टता नहीं है कि ऐसा क्यों हो सकता है।

43.1 धारा 218 यह प्रदान करती है कि, पहले, प्रत्येक अलग अपराध के लिए अलग आरोप होना चाहिए; और दूसरे, प्रत्येक ऐसे आरोप के लिए अलग मुकदमा होना चाहिए, सिवाय उन चार मामलों के जो धारा 219, 220, 221 और 223 में बताए गए हैं।

43.2 धारा 219 यह प्रदान करती है कि एक ही प्रकार के तीन अपराधों के तीन आरोपों को एक साल के भीतर एक साथ लिया जा सकता है। यह धारा केवल तब संयुक्त मुकदमे की बात करती है, जब अपराध मूल रूप से सरल प्रकार के हों और इनसे जुड़े विभिन्न आरोपों की ढेर सारी व्यवस्था की आवश्यकता न हो।

43.3 धारा 220 उन मामलों से संबंधित है, जब एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के आरोपों का मिश्रण किया जाता है। यह तब लागू होती है, जब अलग-अलग अपराध एक ही घटना का हिस्सा बनते हैं और उसी व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं, तो उसे एक मुकदमे में हर अपराध के लिए आरोपित और परीक्षण किया जा सकता है।

43.4 धारा 221 उन मामलों के लिए है, जहां यह संदेह होता है कि कौन सा अपराध किया गया है। यदि एक ही कार्य या कार्यों की श्रृंखला इस प्रकार की हो कि यह संदेह हो कि उनमें से कौन से अपराध को साबित किए गए तथ्य पूरा करेंगे, तो आरोप सभी अपराधों के लिए या वैकल्पिक आरोपों के रूप में तैयार किए जा सकते हैं। मुकदमे में, यदि यह साबित हो जाता है कि आरोपी ने अपराध किया है, तो उसे दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उसे उस अपराध का आरोप न लगाया गया हो।

43.5 धारा 222 उन मामलों में लागू होती है, जिसमें अपराध का आरोप एक ऐसे अपराध से संबंधित है, जिसमें कई विशेषताएँ होती हैं, जिनमें से कुछ का संयोजन ही एक संपूर्ण हल्का अपराध बनाता है।

43.6 धारा 223 उन मामलों में आरोपों के मिश्रण की अनुमति देती है, जिनमें एक से अधिक आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप एक ही मुकदमे में हो सकते हैं। यह उन व्यक्तियों की बहुलता से संबंधित है, जिन्हें एक साथ मुकदमे में लाया जा सकता है, यानी, एक से अधिक व्यक्तियों का संयुक्त मुकदमा।

43.7 धारा 224 उन मामलों के लिए है, जिसमें किसी एक आरोप पर सजा होने के बाद बाकी आरोपों को वापस लिया जा सकता है।

44. धारा 218 से 222 तक उसी व्यक्ति के खिलाफ उसी मुकदमे में आरोपों के मिलाने से संबंधित हैं। धारा 223 व्यक्तियों की बहुलता से संबंधित है, यानी, एक ही मुकदमे में एक से अधिक आरोपियों को सम्मिलित करना। हम इस संदर्भ में इन प्रावधानों के आवेदन को स्पष्ट करने के लिए कुछ निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं।

44.1 ***बलबीर बनाम राज्य हरियाणा***[63] में, तीन न्यायधीशों की एक पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की थी: "11. ... उपर्युक्त दोनों धाराओं में मुख्य शर्त यह है कि व्यक्तियों को या तो एक ही अपराध का आरोपी होना चाहिए या फिर वे अलग-अलग अपराधों के आरोपी हों, जो 'एक ही घटना के दौरान किए गए हों'। प्रयुक्त शब्द 'एक ही घटना के दौरान किए गए' यह कहने के समान नहीं है 'एक ही विषय पर'। यह महत्वपूर्ण है कि इसी शब्दावली का प्रयोग धारा 220(1) में भी किया गया है [पुरानी संहिता की धारा 235(1) के अनुरूप]। धारा 223 में प्रयुक्त 'एक ही घटना के दौरान किए गए' शब्द का अर्थ, धारा 223(1) में प्रयुक्त शब्द से अधिक भिन्न नहीं है [सिक 235(1)]। इसे इस न्यायालय ने राज्य ए.पी. बनाम चीमलापति गनेश्वर राव [ए.आई.आर. 1963 एससी 1850 : (1964) 3 एससीआर 297] में इस प्रकार समझा है। इस निर्णय में निम्नलिखित अवलोकन सन्दर्भ के योग्य है:"

"जो कार्यों की श्रंखला एक घटना का गठन करती है, वे एकदूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए और - यदि इनमें से कुछ स्वतंत्र रूप से खड़े होते हैं, तो वे एक ही घटना का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि वे एक अलग घटना या घटनाओं का गठन करेंगे। इसलिए, भले ही धारा 235(1) में केवल 'एक ही घटना' शब्द का उपयोग किया गया होता, तब इसका मतलब एक ऐसी घटना होता, जो या तो

---

63 [1999] सप. 4 एससीआर 120 : (2000) 1 एससीसी 285

एकल क्रिया से बनी होती, या फिर जुड़ी हुई क्रियाओं की एक श्रृंखला से। धारा 239 के उपबंध)a), (c) और)d) में तथा धारा 235(1) में प्रयुक्त 'एक ही घटना' शब्द का वही अर्थ होना चाहिए, जैसा कि सामान्य रूप से क़ानून के निर्माण की नियमावली में निर्धारित है।"

12. "कई अपराधों को एक ही घटना का हिस्सा बनाने के लिए, जो परीक्षण लागू करना है वह यह है कि क्या वे एकदूसरे से उद्देश्य या कारण और प्रभाव के सं-दर्भ में इस तरह जुड़े हुए हैं, या प्रधान और सहायक के रूप में, जिससे एक निरंतर क्रिया का परिणाम होता है। इस प्रकार, जब उद्देश्य या योजना की समानता हो, जब क्रिया की निरंतरता हो, तो वे सभी व्यक्ति जो इसमें शामिल हैं, उन्हें 'एक ही घटना के दौरान किए गए' एक ही या विभिन्न अपराधों का आरोपी बनाया जा सकता है।"

44.2 ***आर. दिनेश कुमार बनाम राज्य64*** में इस न्यायालय ने 'घटना' के पहलू पर निम्नलिखित रूप में विचार किया:

"...19.3. इस न्यायालय ने यह देखते हुए कि 'एक ही घटना' शब्द धारा 1 में परिभाषित नहीं है, यह राय व्यक्त की कि इस शब्द का अर्थ प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करना चाहिए। हालांकि, इस न्यायालय ने यह संकेत दिया कि जब समय, स्थान या उद्देश्य और योजना की एकता या क्रियाओं की निरंतरता के संदर्भ में कुछ घटनाओं की श्रृंखला हो, तो यह माना जा सकता है कि वे एक ही घटना का हिस्सा हैं। इस न्यायालय ने यह भी चेतावनी दी कि उपर्युक्त सभी तत्वों का एक साथ अस्तित्व में होना जरूरी नहीं है, ताकि एक घटना को 'एक ही घटना' माना जा सके। 20. हमारे अनुसार, 'गणेशवरा राव' मामले में घोषित सिद्धांत यह है कि जब कई व्यक्तियों पर कई अलग-अलग अपराध करने का आरोप है, जो पूरी तरह से अप्रतिबद्ध नहीं होते, तो एक संयुक्त परीक्षण संभव हो सकता है, जब तक कि ऐसा संयुक्त परीक्षण आरोपियों को अपनी रक्षा में कोई कठिनाई या संकोच न पैदा करे।"

44.3 ***नसीब सिंह बनाम राज्य पंजाब65*** में, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ (जिन्होंने उस समय इस निर्णय में अपनी राय दी) ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए संयुक्त या अलग-अलग परीक्षणों के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया:

---

64 [2015] 5 एससीआर 605 : (2015) 7 एससीसी 497

65 [2021] 13 एससीआर 566 : (2022) 2 एससीसी 89

"51.1. धारा 218 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए विभिन्न अपराधों के लिए अलग-अलग परीक्षण किए जाएंगे। धारा 219-221 इस सामान्य नियम के अपवाद प्रदान करती हैं। यदि कोई व्यक्ति इन अपवादों के तहत आता है, तो उस व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के लिए संयुक्त परीक्षण किया जा सकता है। इसी तरह, धारा 223 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए आरोपित व्यक्तियों का संयुक्त परीक्षण किया जा सकता है यदि इस प्रावधान के किसी भी खंड को अलग-अलग या संयोजन में पूरा किया जाए।

51.2. धारा 218-223 में उल्लिखित सिद्धांतों को संयुक्त और अलग परीक्षणों पर लागू करते समय, परीक्षण न्यायालय को दो-प्रमुख परीक्षण लागू करना चाहिए, अर्थात (i) क्या संयुक्त/अलग परीक्षण से आरोपी की रक्षा में हानि होगी; और/या (ii) क्या संयुक्त/अलग परीक्षण से न्यायिक विलंब होगा।

51.3. संयुक्त परीक्षण की संभावना को परीक्षण की शुरुआत में निर्धारित किया जाना चाहिए, न कि परीक्षण के परिणाम के आधार पर। अपीलीय न्यायालय केवल इस आधार पर यह निर्धारित कर सकता है कि क्या अलग/संयुक्त परीक्षण किया जाना चाहिए था, कि क्या परीक्षण से आरोपी या अभियोजन पक्ष के अधिकारों को हानि हुई थी या नहीं।

51.4. चूंकि उन प्रावधानों में अपवाद का समावेश करते समय "हो सकता है" शब्द का प्रयोग किया गया है, संयुक्त परीक्षण करना आमतौर पर कानून के खिलाफ नहीं है, भले ही संयुक्त परीक्षण किया जा सकता था, जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि इससे न्याय का हनन हुआ।

51.5. आरोपी की सजा या बरी होने का आदेश केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि एक संयुक्त या अलग परीक्षण होने की संभावना थी। सजा या बरी होने के आदेश को रद्द करने के लिए यह साबित करना होगा कि पक्षों के अधिकारों को संयुक्त या अलग परीक्षण के कारण हानि हुई थी, जैसा कि मामला हो।"

अपीलकर्ता का मामला, जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है, बाद की श्रेणी में आता है, अर्थात् एक ही परीक्षण में कई व्यक्ति (अपीलकर्ता ए-17 हैं, कुल 20 आरोपियों में से)। यह स्थापित किया गया है कि संयुक्त या अलग परीक्षण का निर्णय परीक्षण के प्रारंभ में परीक्षण न्यायाधीश द्वारा लिया जाना चाहिए, जिसमें (अ) पक्षपाती होने की संभावना और (ब) यदि कोई न्यायिक विलंब हो, इन दोनों पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, धारा 223 की भाषा निदेशात्मक प्रकृति की है, जिसे 'हो सकता है' शब्द के प्रयोग से संकेतित किया गया है।

45. नसीब सिंह (उपरोक्त) के अनुसार, अलग-अलग परीक्षण तब तक कानून के विपरीत नहीं होगा जब तक न्याय का हनन साबित नहीं किया जा सकता। इसी तरह, हमारा मानना है कि यदि उपरोक्त दो कारकों पर विचार करने के बाद संयुक्त परीक्षण किया गया हो, तो इसे स्वाभाविक रूप से पक्षपातपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

46. यह आरोप लगाया गया है कि दिनेश गोप (ए-6), जो पीएलएफआइ का प्रमुख है, विभिन्न व्यक्तियों से धन उगाही करता है और इस कंपनी (ए-20), जिसका वर्तमान अपीलकर्ता निदेशक है, का उपयोग ऐसे गैरकानूनी कार्यों से प्राप्त धन को वैध बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि, अपीलकर्ता का तर्क है कि ए-6 पर लगाए गए आरोपों और उन लेनदेन के बीच कोई संबंध नहीं है, जिनके कारण उसे आरोपी बनाया गया है। वहीं, अभियोजन का कहना है कि ए-6 और ए-17 दोनों ही एक ही, सतत और चल रहे लेनदेन का हिस्सा हैं। वास्तव में मामला क्या है, यह साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण में तय किया जाना है, न कि इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा। ***उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पारस नाथ सिंह[66]*** में न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:
"8. ... जैसा कि यह प्रावधान स्वयं निर्धारित करता है कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय, स्वीकृति, या आदेश अमान्य नहीं होगा, जब तक कि यह प्रदर्शित न किया जाए कि न्याय की विफलता वास्तव में किसी त्रुटि, चूक या आरोपों में गड़बड़ी (जिसमें आरोपों का गलत संयोजन शामिल है) के कारण हुई हो। स्वाभाविक रूप से, यह दायित्व अभियुक्त पर है कि वह दिखाए कि वास्तव में न्याय की विफलता हुई है।"

इसलिए, हम यह मुद्दा अपीलकर्ताओं पर छोड़ते हैं कि वे इसे ट्रायल जज के समक्ष उठाएं, जो यदि ऐसा प्रश्न उठाया जाता है, तो उसे उपयुक्त चरण पर शीघ्रता से निर्णय करेंगे।

मुद्दा संख्या 4 – क्या धारा 22ए अपीलकर्ता पर लागू होती है?

47. यूएपीए की धारा 22ए इस प्रकार है:

"**22ए. कंपनियों द्वारा अपराध—**

(1) यदि इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी द्वारा अपराध किया गया है, तो वह कंपनी और वह प्रत्येक व्यक्ति (जिसमें कंपनी के प्रमोटर भी शामिल हैं) जो अपराध के समय कंपनी के कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी था, अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही

---

66 [2009] 8 एससीआर 85 : (2009) 6 एससीसी 372

की जाएगी तथा उसे इस अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा: प्रावधान: इस उपधारा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति (जिसमें प्रमोटर भी शामिल हैं) को दंडित करने के लिए उत्तरदायी ठहराए, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसके ज्ञान के बिना हुआ है या उसने अपराध को रोकने के लिए उचित सावधानी बरती थी।

(2) उपधारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि यह साबित होता है कि अपराध कंपनी के प्रमोटर, निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति, मिलीभगत या उपेक्षा के कारण किया गया है, तो ऐसे प्रमोटर, निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी तथा उन्हें दंडित किया जाएगा। व्याख्या—

इस धारा के प्रयोजन के लिए: (अ) "कंपनी" का अर्थ है कोई भी कॉर्पोरेट निकाय और इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ भी शामिल है; और (ब) "निदेशक" का अर्थ फर्म के संदर्भ में फर्म का भागीदार होता है।"

48. धारा 22ए लागू होने के लिए: (a) अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया होना चाहिए; (b) अपराध के समय जो व्यक्ति कंपनी के कार्यों का नियंत्रण या उनके लिए उत्तरदायी थे, उन्हें अपराधी माना जाएगा; (c) ऐसा व्यक्ति, जो (b) के तहत दोषी माना गया हो, दोषमुक्त हो सकता है यदि वह यह साबित कर सके कि: (i) यह कृत्य उसके ज्ञान में नहीं था; (ii) उसने इस अपराध को रोकने के लिए उचित सावधानी बरती थी। यह धारा आगे यह प्रावधान करती है कि यदि यह साबित हो जाए कि कंपनी द्वारा किया गया अपराध: (1) किसी व्यक्ति की सहमति से हुआ; (2) किसी की मिलीभगत से हुआ; (3) प्रमोटर, निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कंपनी के किसी अन्य अधिकारी की लापरवाही के कारण हुआ है, तो उन्हें अपराधी ठहराया जाएगा।

49. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामला यह है कि वह, जो कथित रूप से ए-20 का निदेशक है, को वैधानिक भाषा द्वारा सुरक्षा प्राप्त है, जो यह प्रदान करती है कि यदि कोई व्यक्ति यह प्रदर्शित और सिद्ध कर सके कि अपराध उसके ज्ञान के बिना किया गया, तो उसे अभियोजन से छूट दी जाएगी। यह छूट अन्य विधानों में भी मान्यता प्राप्त है। हम 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम67 की धारा 138 और 141 के संदर्भ में इस न्यायालय के निर्णयों का समर्थन ले सकते हैं, क्योंकि ये धाराएँ समान रूप से शब्दित और अभिव्यक्त हैं।

---

67. संक्षिप्त में 'एनआइ अधिनियम'

"141. **कंपनियों द्वारा अपराध—**

(1) यदि धारा 138 के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, तो वह प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कार्यों के संचालन के लिए प्रभारी था और जिम्मेदार था, साथ ही कंपनी भी, अपराध के लिए दोषी मानी जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे दंडित किया जाएगा:

प्रदत्त है कि: इस उपधारा में निहित कुछ भी ऐसा व्यक्ति को दंड का पात्र नहीं बनाएगा, यदि वह यह सिद्ध कर सके कि अपराध उसके ज्ञान के बिना किया गया था, या उसने ऐसे अपराध की रोकथाम के लिए सभी उचित सावधानी बरती थी।

यह भी प्रदत्त है कि: जहां किसी व्यक्ति को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी कार्यालय या रोजगार के तहत या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रण में वित्तीय निगम द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नामांकित किया गया है, तो उसे इस अध्याय के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है और यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपराध किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कंपनी के अन्य अधिकारी की सहमति, मिलीभगत या उपेक्षा के कारण किया गया है, तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दंडित किया जाएगा।

व्याख्या।— इस धारा के प्रयोजन के लिए:

(a) "कंपनी" का अर्थ किसी भी निगम से है और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और
(b) "निदेशक" का, किसी फर्म के संबंध में, अर्थ फर्म का भागीदार होता है।

49.1. ***एस.एम.एस. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला(68)*** के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह माना कि केवल वही व्यक्ति, जो कंपनी के मामलों का प्रभारी हो, अर्थात निदेशक, प्रबंधक, या सचिव और साथ ही अपराध करने के कृत्य से संबंधित हो, इस धारा के तहत उत्तरदायी होगा। इसका प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

---

68 [2007] 2 एससीआर 862 : (2005) 8 एससीसी 89

"10. …जो आवश्यक है, वह यह है कि जिन व्यक्तियों को धारा 141 के तहत आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराने की बात की जा रही है, उन्हें अपराध किए जाने के समय कंपनी के कार्यों के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार होना चाहिए। कंपनी से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति इस प्रावधान के दायरे में नहीं आएंगे। केवल वे व्यक्ति, जो अपराध के समय कंपनी के कार्यों के संचालन के प्रभारी और जिम्मेदार थे, वे ही आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि कोई कंपनी का निदेशक, जो न तो प्रभारी था और न ही कंपनी के कार्यों के संचालन के लिए जिम्मेदार था, प्रासंगिक समय पर इस प्रावधान के तहत उत्तरदायी नहीं होगा। उत्तरदायित्व उस समय कंपनी के कार्यों के संचालन के प्रभारी और जिम्मेदार होने से उत्पन्न होता है, जब अपराध किया गया था, और यह केवल किसी पदनाम या कंपनी में पद धारण करने के आधार पर नहीं है। इसके विपरीत, कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने कंपनी में कोई पद या पदनाम नहीं धारण किया है, उत्तरदायी हो सकता है यदि वह यह साबित करता है कि वह अपराध के समय कंपनी के कार्यों के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार था। उत्तरदायित्व इस बात पर निर्भर करता है कि किसी ने कंपनी के मामलों में क्या भूमिका निभाई और यह पदनाम या स्थिति पर आधारित नहीं है। यदि केवल निदेशक, प्रबंधक या सचिव होना आपराधिक उत्तरदायित्व के लिए पर्याप्त होता, तो धारा ने यही कहा होता। "हर व्यक्ति" के बजाय, धारा में कहा गया होता, "कंपनी में हर निदेशक, प्रबंधक या सचिव उत्तरदायी है"। विधायिका जानती है कि यह आपराधिक उत्तरदायित्व का मामला है, जिसका मतलब है कि संबंधित व्यक्ति के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए, केवल वही व्यक्ति, जो प्रासंगिक समय पर अपराध के कृत्य से जुड़ा हुआ हो, उसे ही कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है।"

49.2 यह कानून की स्थापित स्थिति है जिसे बाद में इस न्यायालय के कई निर्णयों में पुनः व्यक्त किया गया है। उदाहरण के तौर पर, हाल ही में ***सुसेला पद्मावथी अम्मा बनाम भारती एयरटेल लिमिटेड***[69] में, जो ***एस.एम.एस. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड*** (उपर्युक्त) का संदर्भ देता है, अपीलकर्ता को धारा 138, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम के तहत अपराधों से मुक्त कर दिया गया। न्यायमूर्ति गवाई ने बेंच की ओर से यह टिप्पणी की:

"21. यह निर्धारित किया गया कि केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी का निदेशक है, यह आवश्यक नहीं है कि वह कंपनी के रोज़मर्रा के कामकाज के बारे में जानता हो। इस न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि कंपनी का निदेशक उसके रोज़मर्रा के मामलों का प्रभारी होता है। इसलिए, यह आवश्यक था कि यह कहा जाए कि कंपनी का निदेशक कंपनी के रोज़मर्रा के मामलों का प्रभारी था या वह कंपनी के मामलों के लिए

---

69 [2024] 3 एससीआर 647 : 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 311

जिम्मेदार था। हालांकि, इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि एक प्रबंध निदेशक या सहायक प्रबंध निदेशक का पद स्थिति में भिन्न हो सकता है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि ये व्यक्ति, जैसे उनके पद का नामकरण बताता है, कंपनी के प्रभारी होते हैं और कंपनी के व्यापार के संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिम्मेदारी से बचने के लिए, उन्हें यह साबित करना होगा कि जब अपराध हुआ था, तो उन्हें उस अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी या उन्होंने अपराध की रोकथाम के लिए सभी उचित सावधानियां बरती थीं।"

[देखें: *एन. रंगाचारी बनाम बीएसएनएल*[70]*; सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम एसियन ग्लोबल लिमिटेड*[71]*; गनमाला सेल्स (पी) लिमिटेड बनाम अनु मेहता*[72]; और **राजेश वीरेन शाह बनाम रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड**[73]]

50. वर्तमान मामले के तथ्यों पर पुनः ध्यान केंद्रित करते हुए, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता जो यह दावा कर रहे हैं कि वे एक निदेशक नहीं हैं, बल्कि एक अनपढ़ व्यक्ति हैं जो एक मुंशी हैं और जिनकी पहचान ए-7 और ए-14 ने चुराई है। इस स्थिति में, इस अदालत के लिए यह निर्णय लेना कि क्या धारा 22ए लागू होती है, इस स्तर पर संभव नहीं है।

51. उपरोक्त की गई चर्चा के परिणामस्वरूप, इस अदालत द्वारा हमारे विचारार्थ प्रस्तुत विधिक प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैं:

51.1. अनुमति की वैधता को पहले उपलब्ध अवसर पर, परीक्षण न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए। यदि ऐसी चुनौती अपील के स्तर पर उठाई जाती है, तो चुनौती उठाने वाले व्यक्ति को यह स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने इसे स्वतंत्र रूप से क्यों उठाया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनौती का दुरुपयोग न हो और कार्यवाही में देरी या रुकावट न हो।

51.2. 2008 नियमों के नियम 3 और 4 में उल्लिखित समयसीमाएं अनिवार्य भाषा में लिखी गई हैं और इसलिए इनका पालन सख्ती से किया जाना चाहिए। यह देखते हुए कि यूंएपीए एक दंडात्मक कानून है, इसका सख्त निर्माण किया जाना चाहिए। कानूनी नियमों के माध्यम से निर्धारित समयसीमाएं कार्यपालिका के अधिकारों पर नियंत्रण रखने का एक तरीका हैं, जो

---

70 [2007] 5 एससीआर 329 : (2007) 5 एससीसी 108

71 [2010] 7 एससीआर 694 : (2010) 11 एससीसी 203

72 [2014] 10 एससीआर 1117 : (2015) 1 एससीसी103

73 (2024) 4 एससीसी 305

अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। अनुमोदन की अनुशंसा करने वाली और अनुमोदन देने वाली दोनों ही प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा स्वतंत्र समीक्षा करना यूएपीए की धारा 45 का अनुपालन करने के लिए आवश्यक पहलू हैं।

52. अगला प्रश्न, जो तथ्यों के विश्लेषण पर निर्भर है, के उत्तर इस प्रकार हैं:

52.1. धारा 218-222, दंड प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। धारा 223 के संदर्भ में, कानून की स्थिति वह है जो पारस नाथ सिंह (सुप्र) में ली गई है। इसलिए, यह अदालत विवेकपूर्ण तरीके से इसे परीक्षण न्यायालय पर छोड़ती है कि यदि ऐसी कोई समस्या परीक्षण न्यायालय में उठाई जाती है तो वह इसका निर्णय ले।

52.2. क्या धारा 22ए के तहत छूट लागू होती है, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे प्रमाण के माध्यम से स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि दावा करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि या तो वह उस कंपनी के मामलों का प्रभारी नहीं था जिसने कथित अपराध किया है, या उसने अपराध की कार्यान्वयन को रोकने के लिए उचित प्रयास किए थे। यह फिर से एक ऐसा मुद्दा है जिसे परीक्षण न्यायालय को विचार करने के लिए छोड़ दिया गया है और इस अदालत को इस स्तर पर इसका निर्णय नहीं लेना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि परीक्षण अभी चल रहा है और काफी हद तक प्रक्रिया हो चुकी है।

उपर्युक्त कारणों से, अपील योग्यता में नहीं है और, अतः, इसे खारिज किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, वह निपटाए जाएंगे।

मामले का परिणाम: अपील खारिज।

† हेडनोट्स द्वारा: निधि जैन

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|